page 1 and 8 July 17_page 1 Mar 25 final ds.qxd 7/17/2026 1:57 AM Page 1

epaper.dehatsandesh.com

3 विधायक ने डीप ड्रेन का किया लोकार्पण

5 आईसीसी वनडे रैंकिंग: अक्षर पटेल आलराउंडरों की टाप 10 की सूची में शामिल

8 18 जुलाई से श्रीनगर में शुरू होगा 9 दिवसीय चिनार पुस्तक महोत्सव

न्यूनतम 25

मौसम जम्मू

अधिकतम 36

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-178 | जम्मू तवी, शुक्रवार 17 जुलाई, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

भविष्य के युद्धों में रणनीतिक अवसंरचना की भूमिका निर्णायक रहेगी : राजनाथ

नयी दिल्ली, 16 जुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अत्याधुनिक हथियारों और आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकियों के बावजूद सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और बंदरगाह जैसे सामरिक अवसंरचना सैन्य अभियानों के लिए भविष्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगी।

श्री सिंह ने गुरुवार को यहां सीमा सड़क संगठन रणनीतिक अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सैनिकों को मोर्चे तक पहुंचाने वाली सड़क भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि सीमा पर तैनात सैनिक, इसलिए अवसंरचना का निर्माण करने वाले भी राष्ट्रीय सुरक्षा के समान रूप से महत्वपूर्ण प्रहरी हैं।

रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन की सराहना करते हुए कहा कि उसने एक साधारण सड़क निर्माण एजेंसी से विश्व के

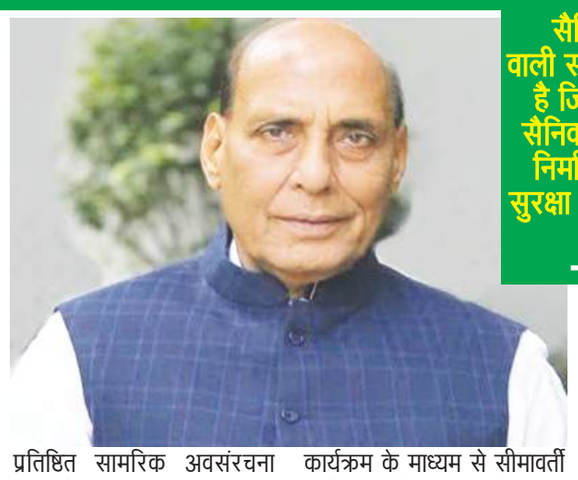

सैनिकों को मोर्चे तक पहुंचाने वाली सड़क भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि सीमा पर तैनात सैनिक, इसलिए अवसंरचना का निर्माण करने वाले भी राष्ट्रीय सुरक्षा के समान रूप से महत्वपूर्ण प्रहरी हैं।

प्रतिष्ठित सामरिक अवसंरचना संगठनों में स्थान बनाया है। उन्होंने अटल सुरंग, सेला सुरंग और उमलिंग ला दर्रा जैसी परियोजनाओं को संगठन की इंजीनियरिंग क्षमता और उत्कृष्ट कार्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक अवसंरचना और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है।

श्री सिंह ने इस अवसर पर सीमा सड़क संगठन की नई डिजिटल परियोजना प्रबंधन और भर्ती प्रणालियों का शुभारंभ किया, संगठन के तीन प्रमुख प्रकाशनों का विमोचन किया, बीआरओ गान का अनावरण किया तथा अवसंरचना विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली परियोजनाओं को सम्मानित किया। दो दिवसीय सम्मेलन में सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक अवसंरचना विकास को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और सतत निर्माण पद्धतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

उपराज्यपाल ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे और दान प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की

बैठक में सत्यापन प्रक्रियाओं, निगरानी तंत्र, बैंकिंग सुरक्षा उपायों और आवधिक लेखापरीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई, जो प्रक्रिया के हर चरण को नियंत्रित करते हैं।

जम्मू, 16 जुलाई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे और दान प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक के दौरान श्रद्धालुओं के चढ़ावे के संग्रह, गिनती, लेखांकन, सुरक्षा और उपयोग की व्यापक समीक्षा की गई। चढ़ावे और दान के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बोर्ड के अधिकारियों ने दान पेटियों, दान काउंटरों, ऑनलाइन प्लेटफार्मों और कीमती धातुओं के रूप में प्राप्त चढ़ावे के सुरक्षित और पारदर्शी प्रबंधन के लिए स्थापित सुदृढ़ प्रणालियों और संस्थागत तंत्रों पर प्रकाश डाला। बैठक में सत्यापन प्रक्रियाओं, निगरानी तंत्र, बैंकिंग सुरक्षा उपायों और आवधिक लेखापरीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई, जो प्रक्रिया के हर चरण को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया कि चढ़ावे और दान से संबंधित सभी वित्तीय लेनदेन निर्धारित बैंकिंग मानदंडों, वैधानिक प्रावधानों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किए जाते हैं।

बोर्ड ने बहुमूल्य धातुओं के रूप में प्राप्त चढ़ावों के प्रबंधन और भंडारण के लिए अपनाए गए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और भारतीय रिज़र्व बैंक और हैदराबाद स्थित भारतीय सरकारी टकसाल सहित प्रतिष्ठित सरकारी अनुमोदित संस्थानों के माध्यम से उनके सुरक्षित परिवहन, प्रसंस्करण और शोधन की भी सराहना की। विस्तृत समीक्षा के बाद बोर्ड ने मौजूदा व्यवस्थाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता पर संतोष व्यक्त किया।

बैठक में मंदिर बोर्ड के सदस्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरिजी महाराज, श्री बालेश्वर राय, डॉ. अशोक भान, श्रीमती सुधा मूर्ति, श्रीमती गुंजन राणा, डॉ. के.के. तलवार, कुलभूषण आहूजा, ललित भासिन, सुरेश कुमार शर्मा, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मनदीप के. भंडारी, सचिन कुमार वैश्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएमवीडीएसबी, आलोक कुमार मौर्य अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएमवीडीएसबी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन माध्यम से कटरा स्थित आध्यात्मिक विकास केंद्र में उपस्थित थे।

खबर संक्षेप

एसआईए के नार्को-टेरर केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आरोप तय किए

श्रीनगर, 16 जुलाई। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) कश्मीर द्वारा जांचे जा रहे एक बड़े नार्को-टेरर केस में आरोप तय कर दिए हैं। इससे पाकिस्तान समर्थित नार्को-टेरर सिंडिकेट के सदस्यों के खिलाफ ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। इन सदस्यों पर नशीले पदार्थों की तस्करी से हुई कमाई के जरिए जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को फंड करने का आरोप है।

एजेंसी द्वारा जारी एक बयान में प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला एफआईआर नंबर 19/2022 से जुड़ा है। इसे अक्टूबर 2022 में पुलिस स्टेशन एसआईए कश्मीर ने दर्ज किया था। यह मामला प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एल ई टी) के पाकिस्तान/पीओजेके स्थित हैंडलर्स द्वारा रची गई सीमा-पार साजिश की विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने के बाद दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि जांच से पता चला है कि नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार से जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती थी। कथित तौर पर इससे हुई कमाई का इस्तेमाल आतंकवाद को फंड करने और केंद्र शासित प्रदेश में टेरर इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए किया जाता था।

प्रवक्ता ने कहा कि जांच में 16 आरोपियों की पहचान की गई जिनमें पाकिस्तान/पीओजेके स्थित चार हैंडलर्स भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में रूबीना नजीर मलिक, इश्फाक अहमद मीर, मुदासिर अहमद पोसवाल, सफीर अहमद मुगल, मोहम्मद राशिद ठक्कर, मोहम्मद रियाज लोहार, जावेद इकबाल ठक्कर उर्फ राजा ठक्कर, अब्दुल राशिद मीर, अब्दुल राशिद भट और बशारत अली पोसवाल शामिल हैं जबकि कुपवाड़ा के अमरोही अरना का सगीर अहमद पोसवाल अभी भी फरार है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान/पीओजेके स्थित जो आरोपी फरार हैं उनकी पहचान तारिक अहमद मलिक उर्फ दिलावर, अलिफ-उद-दीन बदाना, मुश्ताक अहमद नाइक उर्फ उस्मान भाई और फिरदौस अहमद डार उर्फ उमर डार के तौर पर हुई है। एक अन्य आरोपी सोपोर के पंजिपोरा का मुश्ताक अहमद मलिक उर्फ राही एक मुठभेड़ में मारा गया था। उन्होंने कहा कि एसआईए कश्मीर ने सभी 16 आरोपियों के खिलाफ छह चार्जशीट दाखिल की हैं और उन तीन घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी हासिल की है जो गिरफ्तारी से बच रहे थे। प्रवक्ता ने बताया कि अभियोजन पक्ष की बात सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट, यू ए पी ए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अभी कोर्ट में मौजूद 10 आरोपियों पर आरोप तय किए।

इन आरोपों में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आपराधिक साजिश, आतंकवादी गतिविधियों, टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवादी संगठनों की सदस्यता, सबूत मिटाने और धोखाधड़ी जैसे अपराध शामिल हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अब सक्षम कोर्ट के सामने अभियोजन पक्ष के सबूत दर्ज करने के साथ मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। एसआईए कश्मीर फरार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी रखे हुए है औरआतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी कर रही है।

जेकेसीए मामले में डॉ. फारूक को पासपोर्ट नवीनीकरण की अदालत से अनुमति, विदेश यात्रा के लिए अलग से लेनी होगी न्यायालय की मंजूरी

श्रीनगर, 16 जुलाई। एक महत्वपूर्ण आदेश में श्रीनगर की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला के पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि विदेश यात्रा करने के लिए उन्हें सक्षम न्यायालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फारूक अहमद भट ने उस याचिका का निस्तारण करते हुए पारित किया, जिसमें डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) फंड गबन मामले के संबंध में अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति मांगी थी। याचिका में डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने अदालत को बताया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, श्रीनगर ने उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले से संबंधित प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के कारण उनके पासपोर्ट आवेदन को लंबित रखा है। उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध चल रही कार्यवाही पहले से ही पुनरीक्षण याचिका में स्थगित है तथा पासपोर्ट का नवीनीकरण लंबित मामले को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।सीबीआई ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जेकेसीए फंड के कथित गबन से संबंधित गंभीर आपराधिक आरोप अभी भी लंबित हैं।

जम्मू-कश्मीर में ईज ऑफ लिविंग के लिए सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण में तेजी लाने पर मुख्य सचिव का जोर

श्रीनगर, 16 जुलाई। मुख्य सचिव अतल डुल्लू ने आज पूर्व आईएएस अधिकारी पी.डब्ल्यू.सी. डेविडार की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न विभागों की सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के रोडमैप पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग** सुनिश्चित करना तथा जम्मू-कश्मीर में अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करना है।

बैठक में सेवा वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जटिल प्रक्रियाओं को समाप्त करने, अनावश्यक अनुपालनों को कम करने तथा सरकारी प्रक्रियाओं के पुनर्गठन पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि नागरिकों, उद्योगों और सरकारी संस्थानों को सेवाएं अधिक तेज, सरल और सुलभ रूप से उपलब्ध कराई जा सकें।

3.55 करोड़ धोखाधड़ी मामले में ईओडब्ल्यू जम्मू की बड़ी कार्रवाई

जम्मू, 16 जुलाई। क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) जम्मू ने 3 करोड़ 55 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को जम्मू के चन्नी डेली इलाके में छापेमारी की।अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई करोड़ों रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामले की जांच के तहत की गई। छापेमारी के दौरान जांच टीम ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जांच की। ईओडब्ल्यू अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच एजेंसी पूरे मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है ताकि कथित धोखाधड़ी में शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके।

कड़ी सुरक्षा के बीच 5,000 से ज्यादा अमरनाथ श्रद्धालुओं का 15वां जत्था जम्मू से रवाना

जम्मू, 16 जुलाई। कड़ी सुरक्षा के बीच 5,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का पंद्रहवां जत्था गुरुवार को जम्मू से कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के दो बेस कैंपों के लिए रवाना हुआ। अब तक 3,880 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर में 3.25 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पूजा-अर्चना कर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्रियों के इस नए जत्थे (5,201 लोग) में 92 साधु, नौ साध्वियां, 3,970 पुरुष, 1,124 महिलाएं, 5 बच्चे और एक ट्रांसजेंडर शामिल थे। वे सीआरपीएफ और पुलिस की सुरक्षा में 251 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। यह काफिला दो अलग-अलग समूहों में रवाना हुआ। बालटाल जाने वाले काफिले में 74 गाड़ियों में 1,745 तीर्थयात्री थे, जो सुबह 3 बजे रवाना हुआ। पहलगाम जाने वाले काफिले में 177 गाड़ियों में 3,456 तीर्थयात्री थे, जो सुबह 3:30 बजे रवाना हुआ। गुरुवार को रवाना हुए जत्थे के साथ 2 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक कुल 1,04,488 तीर्थयात्री जम्मू बेस कैंप से कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। यात्रा के लिए निकलते समय श्रद्धालुओं के बम बम भोले, हर हर महादेव और जय बर्फानी बाबा की के जयकारों से भगवती नगर बेस कैंप गूंज उठा। कई तीर्थयात्रियों ने यात्रा के सुचारू संचालन के लिए की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया।

जो लोग सच में जम्मू कश्मीर की परवाह करते हैं, वे 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हमारे साथ जुड़ेंगे : मुख्यमंत्री के सलाहकार

श्रीनगर, 16 जुलाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने गुरुवार को कहा कि पार्टी 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना प्रस्तावित कार्यक्रम करेगी चाहे इसके लिए इजाज़त मिले या न मिले। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जो लोग सच में जम्मू-कश्मीर की परवाह करते हैं और वहां के लोगों के साथ खड़े हैं वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी हेडक्वार्टर नवा-ए-सुबह में सीनियर एनसी नेता डॉ. शेख मुस्तफा कमाल की याद में आयोजित शोक सभा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए वानी ने कहा कि पार्टी लीडरशिप और कार्यकर्ता तय कार्यक्रम से पहले ही नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि इजाज़त मिले या न मिले हमारा कार्यक्रम होगा। इसका पूरा शेड्यूल सही समय पर बताया जाएगा।

जब उनसे उन खबरों के बारे में पूछा गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को न्योता भेजा गया है तो वानी ने कहा कि 20 जुलाई को ही साफ हो पाएगा कि कार्यक्रम में कौन-कौन शामिल होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग सच में जम्मू-कश्मीर की परवाह करते हैं वहां के लोगों के प्रति हमदर्दी रखते हैं और उनके साथ खड़े हैं वे ज़रूर जंतर-मंतर पर हमारे साथ शामिल होंगे।

वानी ने फिर कहा कि जम्मू-कश्मीर का संवैधानिक दर्जा और छीनी गई गारंटियां वापस पाना नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद है। उन्होंने कहा कि इस मकसद को पाने के लिए राज्य का दर्जा बहाल करना ज़रूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों ने चुनी हुई सरकार के लिए वोट दिया था न कि सत्ता के दो केंद्रों के लिए। डॉ. कमाल को याद करते हुए वानी ने उन्हें एक विनम्र नेता, समझदार राजनीतिक विश्लेषक और धर्म की गहरी जानकारी रखने वाला विद्वान बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. कमाल को जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक इतिहास की गहरी समझ थी और वे सालों तक अहम राजनीतिक घटनाक्रमों से गहराई से जुड़े रहे।

कर्मचारियों के प्रमोशन की जांच करने और सिफारिश करने के लिए विभागीय प्रमोशन समिति गठित

श्रीनगर, 16 जुलाई। जम्मू-कश्मीर विधानसभा सचिवालय ने लागू सेवा भर्ती नियमों और सरकारी निर्देशों के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन की जांच करने और उनकी सिफारिश करने के लिए एक विभागीय प्रमोशन समिति का गठन किया है। यह समिति जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सचिव की अध्यक्षता में काम करेगी। आदेश के अनुसार समिति में कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग का एक प्रतिनिधि और विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इनमें अतिरिक्त सचिव बिलाल अहमद भट, उप सचिव पृथ्वी राज, लेखा अधिकारी संजय कौल, अवर सचिव शब्बीर अहमद वानी, माननीय अध्यक्ष के पीआरओ इकबाल गुल वानी और सहायक निदेशक सैयद अहमद वानी सदस्य होंगे। आदेश में कहा गया है कि समिति को निर्धारित भर्ती नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार फंक्शनल और नॉन-फंक्शनल (इन-सिटू) प्रमोशन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की पात्रता की जांच और समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।

समिति लागू नियमों के अनुसार और सक्षम अधिकारी की मंजूरी के अधीन ही प्रमोशन के लिए सिफारिशें करेगी। इसके अलावा समिति को उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्लेसमेंट प्रमोशन को नियमित और कन्फर्म करने और उन्हें उचित ग्रेड देने की सिफारिश करने का काम भी सौंपा गया है जिन्हें 24 फरवरी 2025 को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था।

लद्दाख में भारत के सबसे ऊंचे व्यावसायिक लिलियम पुष्प खेती क्षेत्र का विकास शुरु

लेह, 16 जुलाई। लद्दाख के लेह जिले के चोगलमसर में भारत के सबसे ऊंचे व्यावसायिक लिलियम पुष्प खेती क्षेत्र के विकास कार्य की शुरुआत हो गई है। यह लद्दाख में अपनी तरह की पहली बड़े पैमाने की पुष्पकृषि (फ्लोरीकल्चर) परियोजना है, जिसका उद्देश्य फूलों की खेती के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर सृजित करना है।

पिछले तीन दिनों के दौरान इस पुष्प क्षेत्र में 50 हजार से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले लिलियम बल्ब लगाए जा चुके हैं। इन पौधों में पहली बार फूल आने की संभावना इस वर्ष सितंबर के पहले सप्ताह में है।

करीब 93 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला चोगलमसर फ्लावर फील्ड सिंधु नदी के तट पर विकसित किया जा रहा है और इसे देश के सबसे बड़े संगठित उच्च हिमालयी पुष्पकृषि पार्कों में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा पुष्प क्षेत्र उत्तराखंड के माना में लगभग 3,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि चोगलमसर फ्लावर पार्क लगभग 3,265 मीटर की ऊंचाई पर विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का क्रियान्वयन सीएसआईआर-हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईएचबीटी), पालमपुर के वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 22 जून 2026 को इस फ्लावर फील्ड की आधारशिला रखी थी। परियोजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले लिलियम फूलों एवं कलियों का उत्पादन करना है, जिनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी मांग और बेहतर कीमत मिलती है। इससे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सहकारी समितियों के माध्यम से लद्दाख के किसानों के लिए आय का एक नया और स्थायी स्रोत विकसित होगा।

कांग्रेस एनसी की राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम में हुई शामिल, सभी पार्टियों से एकजुट होने की अपील की

श्रीनगर, 16 जुलाई। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम अहमद मीर ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस जंतर-मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना लोगों का मुद्दा है और यह किसी एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित नहीं है।

पत्रकारों से बात करते हुए मीर ने कहा कि कांग्रेस ने 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों का लगातार विरोध किया है और हर मंच पर जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मौका होने के बावजूद मंत्री पद न लेने का फैसला किया क्योंकि उनका मानना था कि लोगों का जनादेश राज्य का दर्जा और चुनी हुई सरकार को शक्तियां बहाल करने के लिए था। उन्होंने कहा कि जब असली शक्तियां ही न हों तो मंत्री बनने का कोई मतलब नहीं है।

20 जुलाई को जंतर-मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन का ज़िक्र करते हुए मीर ने कहा कि कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और कार्यक्रम में हिस्सा लेगी।

उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की और कहा कि किसी को भी एक साझा मकसद के रास्ते में अहंकार को नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होना चाहिए और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक साझा आवाज़ उठानी चाहिए।

मीर ने लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण आंदोलन का भी समर्थन किया और कहा कि लद्दाख के लोगों ने बिना हिंसा का सहारा लिए लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी मांगें रखी हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई भी लोगों की भलाई के लिए शांति से काम कर रहा है वह समर्थन का हकदार है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर कांग्रेस 19 जुलाई को जम्मू में एक बड़ा हमारी रियासत, हमारा हक कार्यक्रम आयोजित करेगी जिसमें पूरे केंद्र शासित प्रदेश से पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि 20 जुलाई को नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगेकांग्रेस एनसी की राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम में हुई शामिल, सभी पार्टियों से एकजुट होने की अपील की

साभार : अशोक कुमार मुनड़ेतिया

नौकरीपेशा लोगों पर मंडराती सेहत की समस्या

आजकल की इस आपाधापी में जहां एक ओर लोग अपने काम की पीछे अपना सारा समय लगा देते हैं वहीं दूसरी ओर अपने इस काम के पीछे अपनी सेहत से भी खिलावाड़ करते रहते हैं। नौकरीपेशा लोग हमेंशा किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त ही रहते हैं।आइए जानते हैं नौकरीपेशा लोगों की सेहत पर कौन सी बड़ी समस्याएं मंडराती हैं।

अवसाद : एक प्रमुख समाचार पत्र में 2011 में प्रकाशित शोध में पाया गया है जो लोग प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक देर तक काम करते हैं उनमें अवसाद का खतरा दोगुना होता है। बहुत अधिक अवसाद ही नौकरीपेशा लोगों को स्ट्रोक या हार्ट अटैक की स्थिति में पहुंचा देता है।

समय से पहले ही बढ़ जाती है उम्र की समस्या : अमेरिकी शोध की मानें तो दफ्तर का तनाव समय से पहले ही बढ़ी उम्र की समस्याओं को बढ़ाता है। काम का तनाव जितना अधिक होता है शरीर में मौजूद टेलोमेयर्स (उम्र से संबंधित विशेष प्रकार का डीएनए) उतना ही कम होता है।

दिल का दौरा : लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी के 2012 के एक शोध की मानें तो जो लोग कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हैं या काम के दबाव में रहते हैं, उन्हें दिल के दौरे का रिस्क 23 प्रतिशत अधिक रहता है।

मधुमेह : एक मेडिसिन पत्र में प्रकाशित शोध की मानें तो नौकरीपेशा महिलाओं को डायबिटीज की आशंका अधिक रहती है। हालांकि शोधकर्ताओं ने अब तक यह नहीं पता लगाया है कि कार्यक्षेत्र और डायबिटीज का पुरुषों से भी उतना ही संबंध है जितना महिलाओं से है।

व्यक्तिगत संबंधों पर भारी है दफ्तर का तनाव : अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के शोध की मानें तो दफ्तर में देर तक काम करने वाले लोगों का तनाव उनके व्यक्तिगत संबंधों को भी भारी पड़ता है। करीब 79 प्रतिशत नौकरीपेशा पुरुषों और 61 प्रतिशत नौकरीपेशा महिलाओं ने इस शोध में माना कि उनके दफ्तर का तनाव उनके व्यक्तिगत संबंधों पर हावी है

कहीं आपका सोफा न बना दे आपको थायरॉइड का मरीज

घर में महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ही सामानों का इस्तमाल रोज करती है।जैसे सोफा, कार्पेट, पर्दे, कागज के सामान आदि।लेकिन इन प्रसाधनों का रोजमर्रा में आपको कितने भी फायदें हों लेकिन इनसे सेहत को एक बड़ा खतरा भी है। हाल में एक शोध में पाया गया है कि इन चीजों के फैब्रिक में विशेष प्रकार के रसायनों का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से महिलाओं में हाइपोथायरॉइड का रिस्क बढ़ जाता है।ताइवान के एन चू कांग अस्पताल के डॉक्टर व शोधकर्ता चेन यू लिन ने बताया कि हमने पशुओं के परीक्षण के आधार पर यह पाया कि सोफा या कालीन के फैब्रिक में इस्तेमाल किए जाने वाले परफ्यूकरोलेटेड केमिकल्स महिलाओं को हाइपोथायरॉइड का शिकार बना सकते हैं। हालांकि अभी तक मानव शरीर पर हमने यह परीक्षण नहीं किया है पर पूरी संभावना है कि इसका संबंध महिलाओं से हो सकता हैं।शोध के दौरान शोधकर्ताओं ने परीक्षण के साथ-साथ जर्नल ऑफ क्लीनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित शोध के दौरान 1,181 प्रतिभागियों का अध्ययन किया और पाया कि जिन लोगों के रक्त में परफ्यूकरोक्टानोएट (पीएफओए) का स्तर अधिक है उन्हें हाइपोथायरॉइड की समस्या की आशंका अधिक है। शोधकर्ताओं का मानना है कि सोफा, कालीन, कॉस्मेटिक्स बनाने में इस्तेमाल किए जाने परफ्यूकरोलेटेड केमिकल्स बहुत धीरे टूटते हैं जिससे ये लंबे समय में वातावरण में घुलते हैं और रक्त में पहुंच जाते हैं।अमेरिका के नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ की निदेशक लिडा बिर्नबॉम के अनुसार थायरॉइड के अलावा इनका संबंध किडनी, लिवर और दिल के रोगों से भी हो सकता है लेकिन फिलहाल इनके प्रत्यक्ष संबंध के बारे में कुछ कहना मुश्किल है।

प्रभावकारी होता है ग्लूट व्यायाम

ऊंची कद काठी, बेहतरीन डोले, शानदार थाईस, चौड़ी छाती और मजबूत बदन हर मर्द की चाहता होती है। लेकिन इस प्रकार के शरीर के लिए आपको व्यायाम में काफी पसीना बहाना पड़ता है। वो भी नियमित तरीके से। व्यायाम करते समय आपको कई बातों का ख्याल करना पड़ता है। मसलन जिस एक्सरसाइज को आप कर रहे हैं वह सही तरीके से हो रही है या नहीं। गलत तरीके से किया गया व्यायाम हानिकारक भी हो सकता है। आइए जानते हैं कुछ विशेष।

ग्लूट एक्सरसाइज

कोई भी व्यायाम शरीर के अन्य अंगों के साथ ही किसी खास अंग पर भी असर डालती है। जैसे आप सीने के लिये व्यायाम कर रहे हैं या डोलो के लिये या फिर कूल्हों के लिये। शरीर के हर हिस्से के लिए अलग व्यायाम है और ये आपके लिए लाभकारी साबित भी होते है। आगे इस लेख में हम बात करते हैं ग्लूट एक्सरसाइज यानी कूल्हों के व्यायाम के फायदों के बारे में।

शरीर के संतुलन में मदद

कूल्हों की मजबूत मांसपेशियां शरीर का संतुलन बनाने में बहुत अहम होती हैं। यदि आपके ग्लूट्स में कमजोरी आ जाती है तो कुछ गंभीर समस्याएं भी हो सकती है। इनमें शरीर का झुकाव, एकाइलेस टेनडिनाइटिस, घुटने की तकलीफ, एड़ी और पिंडली में दर्द आदि हैं। यानी ग्लूटस एक्सरसाइज आपको भविष्य की आशंकाओं से बचाती हैं। धावकों के लिए ग्लूटस बेहद जरूरी होती है, इससे उनके शारीरिक केंद्रक, कूल्हे और कमर को मजबूती मिलती है।

मजबूत शरीर

मजबूत शरीर के लिए कूल्हों की मांसपेशियों का चुस्त होना बहुत जरूरी है। कूल्हों का आकार और मजबूती इनकी तीन मशल्स पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी दिनचर्या में ग्लूटस एक्सरसाइज को शामिल कर लेंगे तो इससे आपके शरीर को मजबूती मिलेगी। फिटनेस विशेषज्ञों के मुताबिक मजबूत कूल्हे आपको ज्यादा वजन उठाने में भी मदद करते हैं।

कमर दर्द में आराम

ग्लूटस एक्सरसाइज कई बार किशोरावस्था या फिर ज्यादा उम्र में होने वाले कमर दर्द से आपको निजात दिलाती हैं। इन्हें करने से न केवल आपके कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है बल्कि आपकी कमर की नसें भी मजबूत होती हैं।

आकर्षक बदन

ग्लूट एक्सरसाइज नियमित करने से आपके कूल्हों की शेप में बदलाव आता है और इसका असर आपके बदन की खूबसूरती पर पड़ता है। शरीर के खूबसूरत दिखाई देने में कूल्हें अहम होते हैं। ज्यादा भारी नितंब भी भद्दे लगते हैं, यदि आप ग्लूटस एक्सरजाइज को नियमित भी नहीं कर पाते हैं तो हफ्ते में एक बार करने की कोशिश करें।

चुस्त

सुबह के वक्त की गई एक्सरसाइज आप दिनभर चुस्त बने रहते हैं। अब यह व्यायाम कूल्हों से संबंधित हो या शरीर के अन्य किसी अंग से आप चुस्त तो रहते ही हैं और तंदुरुस्त भी।

यदि आपका काम लंबे समय तक बैठे रहने वाला हैं तो ग्लूटस एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। अगर आप इसे नियमित नहीं कर पाते तो हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर करें।

जांघों की मजबूती

ग्लूटस एक्सरसाइज आपकी जांघों को भी मजबूत बनाती हैं। यदि आपकी जांघें मजबूत हैं तो आपका बदन देखने में आकर्षक लगता है। कूल्हों का व्यायाम करने से आपके बटक के आकार में परिवर्तन होगा और जांघें मजबूत होंगी।

बीमारी से बचाव

आप किसी भी प्रकार का व्यायाम करें, उसका सबसे ज्यादा फायदा यहीं होता है कि ये आपका बीमारियों से बचाव करता है। ग्लूटस एक्सरसाइज भी आपका बीमारियों से बचाव करती हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

कृषि विभाग ने मिशन मोड अभियान शुरू किया, डंसाल और नगरोटा में 5,600 हरड़ के पौधे लगाए

डंसाल (जम्मू), 16 जुलाई।* औषधीय पौधों की खेती और सतत कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उप मंडलीय कृषि कार्यालय, डंसाल ने **समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)** की परियोजना **पी-5 - औषधीय एवं सुगंधित पौधों (एमएपी) के प्रोत्साहन** के तहत 5,600 हरड़ (टर्मिनेलिया चेबुला) के पौधों का सफलतापूर्वक रोपण एवं वितरण किया।

यह मिशन मोड पौधारोपण अभियान पिछले वर्ष प्रतिकूल मौसम के कारण क्षतिग्रस्त हुई हरड़ की पौधों की भरपाई के उद्देश्य से चलाया गया। इसके तहत लाभार्थी किसानों को नए एवं स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराए गए, ताकि पौधारोपण में आई कमी को पूरा किया जा सके और पौधों की उचित संख्या सुनिश्चित करते हुए एमएपी परियोजना की दीर्घकालिक सफलता को मजबूत बनाया जा सके।

यह कार्यक्रम उप मंडलीय कृषि अधिकारी (एसडीएओ) डंसाल अश्वनी गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इसका संचालन कृषि निदेशक जम्मू अनिल गुप्ता के निर्देशों के अनुसार मुख्य कृषि अधिकारी जम्मू मनोहर लाल शर्मा तथा जिला कृषि अधिकारी (विस्तार) जम्मू विनोद खजूरिया के मार्गदर्शन में किया गया।

कुल 5,600 पौधों में से 2,750-2,750 पौधे क्रमशः नगरोटा और डंसाल ब्लॉकों में किसानों के खेतों में रोपण के लिए वितरित किए गए। लगभग 2.5 से 3 फुट ऊंचाई वाले इन पौधों की आपूर्ति इस उद्देश्य से की गई कि उनका बेहतर विकास हो तथा प्रारंभिक अवस्था में उनकी वृद्धि स्वस्थ एवं मजबूत रहे।

वैज्ञानिक तरीके से पौधारोपण सुनिश्चित करने के लिए एमएपी योजना के नोडल अधिकारी एवं एसएमएस (एसडीएल) प्रणव चड्ढा ने किसानों को स्थल चयन, गड्ढों की तैयारी, पौधों के बीच उचित दूरी, पोषक तत्व प्रबंधन, रोपण तकनीक तथा पौधों की देखभाल संबंधी तकनीकी जानकारी प्रदान की। उन्होंने किसानों को सिंचाई, मल्चिंग, पौधों को सहारा देने, आवारा पशुओं से सुरक्षा तथा नियमित निगरानी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी, ताकि पौधों की जीवित रहने की दर में वृद्धि हो सके।

जम्मू मंडल के पंपोर में दूसरा गुड्स शेड शुरू, अनंतनाग के बाद कश्मीर घाटी को मिली बड़ी सौगात

जम्मू, 16 जुलाई 2026। जम्मू मंडल में यात्रियों के साथ-साथ माल यातायात को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार को नई उड़ान देने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे, जम्मू मंडल ने बारामूला-संगलदान रेल खंड में स्थित *पंपोर रेलवे स्टेशन* पर नए गुड्स शेड का शुभारंभ किया है। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के पश्चात यह गुड्स शेड तत्काल प्रभाव से कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। यह अनंतनाग के बाद जम्मू मंडल के अंतर्गत कश्मीर घाटी का दूसरा गुड्स शेड* है, जो क्षेत्र के आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नव निर्मित पंपोर गुड्स शेड पर प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक कार्य संचालित किया जाएगा। यहां आधा रेक की सुविधा उपलब्ध है और आवक एवं जावक दोनों प्रकार के माल की बुकिंग की जा सकेगी। पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक और कोयले को छोड़कर सभी प्रकार की वस्तुओं को यहां से बुक किया जा सकता है। गुड्स शेड में सभी परिचालन एवं वाणिज्यिक नियमों के साथ-साथ ह्नत्रञ्ज एवं संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का कड़ाई

से पालन सुनिश्चित किया गया है। यह गौरव का विषय है कि गुड्स शेड के शुरू होते ही 15 जुलाई को ही पंपोर के लिए पहली बार दो मालगाड़ियों के इंडेंट प्राप्त हुए हैं।* इसमें एक इंडेंट अंबाला मंडल के *भारतगढ़ रेलवे स्टेशन* से *21 BCN वैगन अल्ट्राटेक सीमेंट* के लिए तथा दूसरा इंडेंट *किरतपुर साहिब* से *21 BCN वैगन ACC एवं अंबुजा सीमेंट* के लिए प्राप्त हुआ है। यह इस बात का प्रमाण है कि नए गुड्स शेड ने शुरू होते ही व्यापारिक समुदाय का विश्वास जीत लिया है। पंपोर में गुड्स शेड की शुरुआत से जम्मू मंडल एवं संपूर्ण कश्मीर घाटी को अनेक लाभ प्राप्त होंगे। अब घाटी के फल उत्पादकों, किसानों और व्यापारियों को अपना माल भेजने के लिए दूरस्थ गुड्स शेड पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे समय और परिवहन लागत दोनों में उल्लेखनीय बचत होगी। इससे स्थानीय स्तर पर लोडिंग-अनलोडिंग, परिवहन और अन्य सहायक सेवाओं में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त अनंतनाग गुड्स शेड पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार में कमी आएगी और माल की निकासी अधिक तेज एवं सुगम हो सकेगी। बेहतर माल आवाजाही से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग भविष्य में यात्री सुविधाओं के और अधिक विकास के लिए किया जाएगा। इस अवसर पर द्ववरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, जम्मू श्री उचित सिंघलद्ग ने कहा कि फ्रजम्मू मंडल व्यापार और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निरंतर प्रयासरत है। पंपोर में गुड्स शेड का शुभारंभ कश्मीर घाटी के व्यापारिक समुदाय के लिए एक बड़ी सौगात है। पहले ही दिन दो इंडेंट प्राप्त होना इस बात का संकेत है कि यह शेड क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

चलती बस में आग लगने से 47 अमरनाथ यात्री बाल-बाल बचे

रामबन, 16 जुलाई (हि.स.)। गुरुवार को रामबन ज़िले के करूल के पास जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अमरनाथ यात्रा के 47 यात्री बाल-बाल बच गए जब उनकी बस में आग लग गई।

अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान से यात्रियों को ले जा रही स्लीपर बस (आरजे27पीसी-9921) श्रीनगर से जम्मू जा रही थी तभी हाईवे पर करूल के पास उसमें आग लग गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस, सीआरपीएफ, सेना, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीमें और स्वयंसेवक मौके पर पहुँचे और बचाव व आग बुझाने का काम शुरू किया। आग की लपटों के बस को अपनी चपेट में लेने से पहले ही ड्राइवर और कंडक्टर समेत सभी 47 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी की मौत या चोट लगने की खबर नहीं है।

उन्होंने कहा कि आग बुझाने के काम के दौरान हाईवे पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ लेकिन आग पर काबू पाने के बाद इसे बहाल कर दिया गया। अधिकारियों ने आगे बताया कि आग लगने के सही कारण की जांच की जा रही है।

पठाना तीर में हजरत सैयद पीर बाबा अकबर शाह बादशाह (रह.) का सालाना उर्स आयोजित

मेंढर 16 जुलाई ।सब-डिवीजन मेंढर के ऐतिहासिक गांव पठाना तीर में हजरत सैयद पीर बाबा अकबर शाह बादशाह (रह.) का सालाना उर्स मुबारक पूरे श्रद्धा, धार्मिक उत्साह और आध्यात्मिक वातावरण के बीच आयोजित किया गया।

इस अवसर पर पीर पंजाल के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों अकीदतमंदों, उलेमा-ए-कराम, मशायख-ए-इज़ाम, हाफिज़-ए-कुरआन, नातख्वानों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर बुजुर्ग-ए-दीन को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उर्स के दौरान पवित्र कुरआन की तिलावत, नात-ए-पाक, ज़िक्रि-ओ-अज़कार, दुआ और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उलेमा-ए-कराम ने हजरत सैयद पीर बाबा अकबर शाह बादशाह (रह.) की धार्मिक, आध्यात्मिक और समाज सुधार संबंधी सेवाओं पर प्रकाश डालते हुए उनकी शिक्षाओं को अपनाने का संदेश दिया।

कार्यक्रम के अंत में देश, जम्मू-कश्मीर में अमन-चैन, आपसी भाईचारे, खुशहाली और मानवता की भलाई के लिए विशेष दुआएं की गईं। उर्स में शामिल श्रद्धालुओं के लिए लंगर का भी विशेष प्रबंध किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद/तबर्रुक ग्रहण किया। पूरे क्षेत्र में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का वातावरण देखने को मिला।

विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने उपराज्यपाल से मुलाकात की

जम्मू, 16 जुलाई (हि.स.)। बाबा अमरनाथजी और बुड्ढाअमरनाथ यात्री नियास के अध्यक्ष श्री पवन कोहली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की और जम्मू-कश्मीर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आगामी बाबा बुड्ढा अमरनाथजी यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया।

इसके बाद श्री कैमर्स डेविड के नेतृत्व में अखिल भारतीय मसीह सेवा दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी उपराज्यपाल से मुलाकात की और ईसाई समुदाय के विभिन्न कल्याणकारी मुद्दों को उठाया

बीबीआईए नेतृत्व के साथ सेमिनार में ईपीएफओ ने विश्वास-2026 योजना के लाभ बताए

सरबजीत सिंह

जम्मू, 16 जुलाई। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-प्रथम (रीजनल पीएफ कमिश्नर-1) सुमीत सिंह ने नव-निर्वाचित अध्यक्ष, बाड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन (बीबीआईए) तरुण सिंगला, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ जम्मू (एफओआईजे) के अध्यक्ष तथा बीबीआईए के पदाधिकारियों के साथ एक संवादात्मक सेमिनार आयोजित किया। इस अवसर पर सुमीत सिंह ने तरुण सिंगला को बीबीआईए का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी और क्षेत्र के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं।

सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ईपीएफओ की तीन प्रमुख योजनाओं तथा हाल ही में शुरू की गई विश्वास-2026 योजना के बारे में जागरूकता फैलाना था। प्रतिभागियों को इस योजना की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराया गया। ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई यह विशेष पहल कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14बी अथवा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 128 के तहत लंबित क्षतिपूर्ति (डैमेज) मामलों के सौहार्दपूर्ण एवं समयबद्ध निपटारे के लिए लागू की गई है।

प्रवर्तन अधिकारी (एनफोर्समेंट ऑफिसर) देविंदर सिंह ने बताया कि विश्वास-2026 योजना 29 जून 2026 से प्रभावी हो चुकी है और यह छह माह की अवधि तक लागू

रहेगी। उन्होंने पात्र संस्थानों से इस एकमुश्त अवसर का लाभ उठाकर लंबित मामलों का समाधान करने तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के अनुपालन को और मजबूत बनाने की अपील की। इस अवसर पर बीबीआईए के अध्यक्ष एवं एफओआईजे के चेयरमैन तरुण सिंगला ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि, विश्वास-2026 योजना की शुरुआत से एसोसिएशन बेहद खुश है। यह समय की आवश्यकता थी, क्योंकि कई संस्थानों में अनजाने कारणों से ईपीएफ अंशदान जमा करने में देरी हुई है। यह योजना जुर्माने में राहत प्रदान करेगी तथा स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कार्यक्रम में बीबीआईए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (सीनियर वाइस प्रेसिडेंट) वीराज मल्होत्रा, सचिव अभिषेक महाजन सहित अन्य पदाधिकारियों एवं उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

विधायक ने डीप ड्रेन का किया लोकार्पण

कठुआ, 16 जुलाई (हि.स.)। कठुआ के विधायक डॉ. भारत भूषण ने गुरूवार को वार्ड नंबर-19 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के समीप डीप कवर ड्रेनेज कार्य का विधिवत लोकार्पण किया। यह कार्य स्थानीय निवासियों की लंबे समय से लंबित मांग थी जिसके पूरा होने से क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विधायक ने बताया कि यह लगभग 85 फीट लंबा डीप कवर ड्रेन उनके विधायक निधि से तैयार किया गया है। यह ड्रेनेज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और लोअर शिवा नगर, नहर रोड के बीच रहने वाले लोगों के लिए काफी राहत लेकर आएगा जहां जलभराव और गंदगी की समस्या बनी रहती थी। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य प्रो. राम मूर्ति शर्मा, सिटी मंडल अध्यक्ष राहुल देव, दिनेश्वर झोनी, प्रदीप शर्मा, सरदार ओंकार सिंह, नरदेव सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

माशा सदर सभा के अध्यक्ष पद के लिए जल्द होंगे चुनाव

जम्मू,, 16 जुलाई (हि.स.)। जम्मू में माशा सदर सभा के अध्यक्ष पद के लिए जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। सभा के पदाधिकारियों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आगामी दिनों में चुनाव की तिथि एवं कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। सभा से जुड़े सदस्यों का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा

उत्तर रेलवे

ई-टेंडर सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए जम्मू तवी स्थित उप मुख्य अभियंता/ब्रिज लाइन द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए खुली निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्रम सं. 1: निविदा सूचना संख्या	OT-04-JAT-26-27
कार्य का नाम	जम्मू मंडल के 63 पुलों पर साइड पाथवे (पैदल निरीक्षण मार्ग) उपलब्ध कराने का कार्य
लगभग लागत	रु. 9,12,28,605.23
बीमा धनराशि	रु. 18,24,600.00
खोलने की तिथि	31.07.2026
IREPS पर बोली शुरू होने की तारीख	17.07.2026
निविदा प्रपत्र की लागत रुपये	रु. 0
पूर्णता अवधि	24 Months
निविदा प्रस्तुत करने व खोलने की तिथि व समय	प्रत्येक के विरुद्ध दर्शाई गई तिथियों को 11:00 बजे तक एवं उसी तिथि को 11:00 बजे के बाद निविदा खोली जाएगी।

वेबसाइट विवरण जहां निविदा के संपूर्ण विवरण देखे व डाउनलोड किए जा सकते हैं: विस्तृत ई-टेंडर सूचना उत्तरी रेलवे वेबसाइट अर्थात www.nr.indianrailways.gov.in (http://www.nr.indianrailways.gov.in) पर उपलब्ध है और निविदा दस्तावेज [www.ireps.gov.in] (http://www.ireps.gov.in) पर उपलब्ध है।

सं.: 04-DYCEBLJAT-2026/27 दिनांक: 08.07.2026 **2346/2026**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

गुरेज विधायक समेत प्रतिनिधिमंडलों ने जावेद राणा से की मुलाकात, जनसमस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई का भरोसा

श्रीनगर, 16 जुलाई (हि.स.)। गुरेज के विधायक नजीर अहमद खान ने विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों के साथ गुरूवार को मंत्री जावेद अहमद राणा से सिविल सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पेयजल, सिंचाई, सड़क संपर्क, बुनियादी ढांचे और अन्य जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। विधायक ने अपने क्षेत्र की प्रमुख विकासात्मक जरूरतों को सामने रखते हुए जनहित परियोजनाओं पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडलों ने भी समस्याओं के त्वरित समाधान और विकास कार्यों को गति देने की अपील की। मंत्री जावेद राणा ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए आश्वासन दिया कि जायज मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित शासन के लिए प्रतिबद्ध है तथा सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

क्र.सं.: – 770-W/01/WA/JAT/2026-27 **दिनांक: 15.07.2026**

Sr.DEN-C/JAT भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से कार्य करते हुए नीचे दी गई निविदाओं के लिए खुली निविदाएं (ई-निविदाएं) आमंत्रित करते हैं और समापन तिथि के साथ **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध हैं 06.08.2026 तक 15:00 घंटे। बोलीदाता अपनी मूल/संशोधित बोलियां अंतिम तिथि एवं समय तक ही जमा कर सकेंगे। इस निविदा के विरुद्ध मैनुअल ऑफर की अनुमति नहीं है, और प्राप्त ऐसे किसी भी मैनुअल ऑफर को अनदेखा कर दिया जाएगा। ठेकेदारों को इस निविदा के लिए निविदा दस्तावेज की लागत और बयाना राशि का भुगतान केवल **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध भुगतान मोड के माध्यम से करने की अनुमति है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि जैसे पोर्टल, डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक, जमा रसीदें, एफडीआर आदि के माध्यम से मैनुअल भुगतान की अनुमति नहीं है। अधिक जानकारी के लिए लॉगऑन करें **www.ireps.gov.in**

निविदा प्रकार	निविदा अनुभाग	निविदा प्रणाली
खुला	कार्य	एकल बोली प्रणाली
निविदा अपलोड करने की तिथि	निविदा प्रारंभ होने की तिथि	निविदा बंद करने की तारीख/समय
15.07.2026	23.07.2026	06.08.2026 15:00

क्र.सं.	टेंडर नं.	निविदा का विवरण
1	19-2026-27-DRM-JAT	जम्मू डिवीजन के अंतर्गत रेलों की USFD टेस्टिंग और SEJ/ISEJ फ्लैंज टेस्टिंग।

विज्ञापन मूल्य (रु.)	बयाना राशि	ऑफर की वैधता	समापन की अवधि
82,30,196.20	164600.00	60 दिन	12 महीने

कार्य की समान प्रकृति:- तकनीकी पात्रता का मूल्यांकन रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 217/Track-P/9 (2) Vol. III dated-07.03.2019 के माध्यम से किया जाएगा।

नोट 1. बोली लगाने से पहले, बोली लगाने वालों को जाँच करनी होगी निविदा के विरुद्ध जारी किसी भी शुद्धिपत्र के लिए।
नोट 2. यदि हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच अर्थ में कोई विसंगति है, तो अंग्रेजी संस्करण को सही और अंतिम माना जाएगा।

2445/26

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

ट्रेड सेल के सह-संयोजक ने एफसीएस एंड सीए निदेशक से मुलाकात की

जम्मू, 16 जुलाई (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (जम्मू-कश्मीर) के ट्रेड सेल के सह-संयोजक एवं त्रिकुटा नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिनव आनंद ने गुरुवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जम्मू के निदेशक राजेश कुमार शावन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच आम जनता, व्यापारियों और उपभोक्ताओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में अभिनव आनंद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपभोक्ता हितों और विभागीय सेवाओं को लेकर अपने सुझाव साझा किए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों और व्यापारियों से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान तथा विभाग और जनता के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने उपभोक्ताओं की सुविधाओं को और प्रभावी बनाने तथा जनहित से जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया।मुलाकात के दौरान निदेशक राजेश कुमार शावन ने विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा तथा आवश्यक सेवाओं के प्रभावी संचालन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। बैठक में जनहित से जुड़े विषयों पर सकारात्मक संवाद हुआ।

रंग तरंग के दूसरे दिन नाटक, संगीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियों ने बांधा समां

जम्मू, 16 जुलाई (हि.स.)। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) जम्मू के वार्षिक परफॉर्मिंग आर्ट्स महोत्सव 'रंग तरंग-2026' के दूसरे दिन मंडपम ऑडिटोरियम में नाटक, संगीत और नृत्य की छह आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम में चार नाटकों, एक लाइव संगीत प्रस्तुति और एक राजस्थानी लोकनृत्य ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।

कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के इन-हाउस म्यूजिक बैंड ने आर्यमन गुहा के नेतृत्व में की जिसकी ऊर्जावान प्रस्तुति को दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन देकर सराहा। इसके बाद व्यंग्य नाटक 'मुगल-ए-मॉडर्न' ने समकालीन अंदाज में मुगलकाल की घटनाओं को हास्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। वहीं 'फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट' ने मानवीय द्वंद्व को प्रभावशाली ढंग से मंच पर उतारा। 'जंगी राम की हवेली' ने सामाजिक सरोकारों को सशक्त अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जबकि 'हैदर' जो विलियम शेक्सपियर के हैमलेट से प्रेरित है ने अपनी भावनात्मक गहराई और अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया।

दिन के कार्यक्रम का समापन राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति पर आधारित रंगारंग नृत्य प्रस्तुति से हुआ जिसने पूरे सभागार को उत्साह से भर दिया। महोत्सव की सभी 18 टीमों को पद्मश्री बलवंत ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया गया है। रंग तरंग-2026 के माध्यम से आईआईएम जम्मू विद्यार्थियों में रचनात्मकता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, नेतृत्व क्षमता और टीमवर्क जैसे गुणों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। महोत्सव आगामी दिनों में भी विभिन्न सांस्कृतिक एवं नाट्य प्रस्तुतियों के साथ जारी रहेगा

पीपुल्स हट फाउंडेशन और डॉ. लाल पैथलैब्स के बीच एमओयू, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगेंगे

जम्मू, 16 जुलाई (हि.स.)। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से पीपुल्स हट फाउंडेशन और डॉ. लाल पैथलैब्स (कलेक्शन सेंटर), बिक्रम चौक जम्मू के बीच गुरुवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह पांच वर्षीय समझौता वर्ष 2031 तक प्रभावी रहेगा जिसके तहत जम्मू क्षेत्र में जरूरतमंद एवं वंचित समुदायों के लिए संयुक्त रूप से निःशुल्क चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य जांच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एमओयू पर पीपुल्स हट फाउंडेशन की ओर से निदेशक एवं सीईओ डॉ. रोहित कौल ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर फाउंडेशन की निदेशक एवं सीओओ रितु कौल तथा मुख्य सलाहकार विकास कौल भी मौजूद रहे। वहीं डॉ. लाल पैथलैब्स (कलेक्शन सेंटर), बिक्रम चौक की ओर से इसकी संचालिका रोशनी मनहास ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

के तहत डॉ. लाल पैथलैब्स शिविरों में प्रशिक्षित फ्लीबोटोमिस्ट, लैब तकनीशियन और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। साथ ही आवश्यक डायग्नोस्टिक उपकरण, सैंपल कलेक्शन किट और रक्त जांच सहित बुनियादी पैथोलॉजी सेवाएं शिविरों एवं अपने केंद्र पर प्रदान करेगा। वहीं पीपुल्स हट फाउंडेशन लाभार्थियों की पहचान, पंजीकरण, शिविरों के आयोजन, जनजागरूकता, समन्वय और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालेगा। दोनों संस्थाओं ने स्पष्ट किया कि यह सहयोग पूरी तरह गैर-व्यावसायिक और मानवीय उद्देश्य पर आधारित है।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER MECHANICAL IRRIGATION DIVISION, AKHNOOR/NOWSHERA

Tele/Fax:01924-253998

Notice InvitingTender

e-NITNo.: -MID/AN/28Dated:-15/07/2026

For and on behalf of The Hon'ble Lt. Governor of Jammu and Kashmir (UT), Executive Engineer, Mechanical Irrigation Division Akhnoor/Nowshera invites e-tenders from Approved contractors/ Registered firms / Workshop owners having experience in Electromechanical Works for following jobs: -

S. No.	Nameofthework	Quantity	Earnest Money(Rs. in Lacs)	Cost of tender document	Period of Completion	Class ofcontractor
01.	Fabrication,providing,fitting, installation testing and commissioning of Slip Ring Assemblies, carbon brushes,carbon brush holders ,locking arrangement along with allied job for 400 HP,HT BHEL make vertical solid shaft 6600 volt motor No 4 & 5 installed at L.I.S. Rajal.	01 Job	02%of the quoted value	Rs. 500	30Days	Registered/Reputedfirms /Workshopownershaving experience in Electromechanical Works

1. 1 The bidding documents can be seen and downloaded fromthe website http://www.jktenders.gov.in from15/07/2026(05:00PM)to 28/07/2026 (02:00 PM). Bidding document contains instruction for bidders, bill of quantities, general terms and condition and other details.
a) The Bids shall be uploaded in electronic format on the website http://www.jktenders.gov.infrom 17/07/2026(10:00AM) to 28/07/2026 (02:00 PM).
b) The complete bidding process will be through electronic mode.
c) A pre-bid meeting will be held on 16/07/2026 (11:30 AM) in the Office of the Executive Engineer, MechanicalIrrigation Division Akhnoor / Nowshera to address any queries from the firms.
d) Cover-I of the bids uploaded on the website up to due date and time will be opened on 29/07/2026(1:00PM) in the Office of the Executive Engineer, Mechanical Irrigation Division Akhnoor / Nowshera in the presence of the bidders who wish to attend. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
e) Furnishing of hard copiesof bids immediately after submission of e-Tenders is dispensed with. The same should be obtained only from the bidders who is declared as L1 after opening of Financial Bids
f) The costof the tenders should be collected by introducing e-challan by simply uploading a copy of necessary treasury challan/Receipt.
2. Similarly, insisting on actual call deposit receipt, a copyof samedulypledgedtothe concerneddepartment should be uploadedby the tenderers. However, before allotting the work or issuing the supply order the original CDR should be obtained and kept on record.
3. Other details can be seen in the bidding document.
4. The guidelines regarding submission of bid in electronic mode can be downloaded from websitehttp://www.jktenders.gov.in
5. The bidders shall go through the tender specificin structions sheet also.

No:-MID/AN/550-54
Dated: - 15-07-2026

DIP/J-5879/26
Dtd: 16-7-2026

Sd/-
Executive Engineer
Mechanica lIrrigation
Division Akhnoor/Nowshera

संपादकीय

अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई

जम्मू–कश्मीर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण लंबे समय से प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है, जबकि समय–समय पर लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान भी चलाए जाते रहे हैं।

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सरकारी भूमि किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति नहीं होती, बल्कि यह जनता की सामूहिक भलाई के लिए होती है और विकासात्मक परियोजनाओं में उपयोग के उद्देश्य से सुरक्षित रखी जाती है। ऐसे में जो लोग सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करते हैं, वे न केवल आम लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं, बल्कि देश के कानून, स्थापित नियमों और संस्थाओं की भी खुली अवहेलना करते हैं।

जम्मू–कश्मीर में बड़े पैमाने पर हो रहे अतिक्रमण को देखते हुए अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई समय की मांग है, ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि सरकार अपनी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।

इसी संदर्भ में सांबा जिला प्रशासन द्वारा पुलिस के सहयोग से बेला मनोहर क्षेत्र में चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान एक सराहनीय कदम है, जिसने दोषियों को कड़ा संदेश देने के साथ–साथ अन्य लोगों को भी ऐसी अवैध गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन की अतिक्रमण विरोधी टीम ने पुलिस के साथ मिलकर सरकारी भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। संबंधित व्यक्ति कथित रूप से मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में भी शामिल बताया गया है। यह कार्रवाई सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की गई, जिससे एक बार फिर प्रशासन की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और कानून के शासन को लागू करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई है।

इस प्रकार की निर्णायक कार्रवाइयाँ अन्य लोगों के लिए भी प्रभावी निवारक सिद्ध हो सकती हैं। जब अतिक्रमण करने वालों को यह विश्वास हो जाएगा कि कानून का उल्लंघन करने पर उन्हें कठोर परिणाम भुगतने होंगे, तो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की प्रवृत्ति में काफी कमी लाई जा सकती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानून का प्रवर्तन पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और भेदभाव रहित हो, ताकि प्रत्येक उल्लंघनकर्ता, चाहे उसका सामाजिक स्तर, प्रभाव या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान कानूनी कार्रवाई का सामना करे। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जम्मू–कश्मीर की एक पुरानी और गंभीर समस्या है, इसलिए इसे जड़ से समाप्त करने के लिए ऐसी कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है।

यह भी आवश्यक है कि ऐसे अभियानों को केवल एक बार की कार्रवाई तक सीमित न रखा जाए, बल्कि नियमित निगरानी, अवैध कब्जों की समय पर पहचान तथा राजस्व विभाग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से लगातार जारी रखा जाए। चूंकि यह समस्या पूरे केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक रूप से फैली हुई है, इसलिए अन्य जिलों में भी इसी प्रकार के अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें और व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। भ्रष्टाचार भी इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे सरकारी भूमि अतिक्रमण के प्रमुख कारणों में से एक है।

भारत में धर्म और राजनीति को अलग क्यों नहीं देखा गया?

दीपक कुमार द्विवेदी

आज के बौद्धिक विमर्शों में एक विचार बार–बार सुनाई देता है, वह है– राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म व्यक्ति का निजी विषय है और राजनीति को उससे अलग रखा जाना चाहिए। यह अवधारणा आधुनिक लोकतांत्रिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा है, किंतु क्या यह भारतीय सभ्यता की मूल चेतना से मेल खाती है? यही प्रश्न आज गंभीर चर्चा की

भारतीय आख्यानों को उनके संदर्भ में समझने की आवश्यकता: भारतीय महाकाव्यों और पुराणों की अनेक कथाओं को केवल आधुनिक वैज्ञानिक कसौटी पर परखने से उनके सांस्कृतिक और दार्शनिक अर्थ छूट जाते हैं। परंपरागत आचार्यों ने इन प्रसंगों को प्रतीकात्मक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में समझाया है। भारतीय ज्ञान परंपरा का आग्रह है कि किसी भी ग्रंथ का मूल्यांकन उसकी अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि में किया जाए, न कि केवल आधुनिक पश्चिमी दृष्टिकोण से। आज भारत तीव्र वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और सांस्कृतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। परिवार व्यवस्था, सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान पर नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

मांग करता है। दरअसल, भारतीय और पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की आधारभूमि अलग–अलग रही है। भारत में जिस धर्म की चर्चा होती है, वह पश्चिम के रिलीजन का पर्याय नहीं है। इसी मूलभूत अंतर की अनदेखी ने लंबे समय से वैचारिक भ्रम उत्पन्न किया है।

भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ किसी विशेष मत, संप्रदाय या पूजा–पद्धति तक सीमित नहीं है। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, 卐धारणाद् धर्ममित्याहु:卐, अर्थात जो समाज और सृष्टि को धारण करे, वही धर्म है। सत्य, न्याय, कर्तव्य, मर्यादा, करुणा और लोककल्याण, ये सभी धर्म के अंग हैं। इसी कारण भारतीय परंपरा में स्वधर्म, राजधर्म, राष्ट्रधर्म और सनातन धर्म जैसी अवधारणाएँ विकसित हुईं। यहाँ धर्म व्यक्ति के निजी जीवन से आगे बढ़कर समाज और राय की नैतिक दिशा निर्धारित करता है।

सेक्युलरिम की उत्पत्ति और भारतीय संदर्भ: यूरोप में सेक्युलरिम का जन्म चर्च और राजसत्ता के बीच सदियों तक चले संघर्ष की पृष्ठभूमि में हुआ। धार्मिक संस्थाओं के राजनीतिक हस्तक्षेप से उत्पन्न टकराव ने राय और चर्च को अलग करने की आवश्यकता पैदा की। भारत का अनुभव इससे बिल्कुल भिन्न रहा। यहाँ राजा स्वयं धर्म के अधीन माना गया। महाभारत से लेकर अर्थशास्त्र और रामायण तक भारतीय ग्रंथों में राजा की शक्ति का स्रोत धर्म और न्याय को माना गया है, न कि उसकी व्यक्तिगत इछा को, इसलिए भारतीय चिंतन में राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि धर्मसम्मत शासन और लोकमंगल रहा है।

राजधर्म – भारतीय शासन–दर्शन की आत्मा: भारतीय इतिहास में आदर्श शासक वही माना गया जिसने राजधर्म का पालन किया। भगवान श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत सुख से ऊपर राजधर्म को रखा। महाभारत में भीष्म, विदुर और श्रीकृष्ण बार–बार शासक को धर्माधारित शासन का उपदेश देते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी स्पष्ट करता है कि राय का अस्तित्व केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की सुरक्षा, न्याय और समृद्धि के लिए है। यही कारण है कि भारतीय राजनीति में धर्म का अर्थ किसी धार्मिक वर्चस्व से अधिक नैतिक उत्तरदायित्व रहा है।

ऋतम् और पुरुषार्थ – संतुलित जीवन का दर्शन: वैदिक साहित्य में समस्त सृष्टि एक शाश्वत व्यवस्था के अधीन मानी गई है, जिसे ऋतम् कहा गया है। इसी व्यवस्था के अनुरूप मानव जीवन के चार पुरुषार्थ– धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष— निर्धारित किए गए। इनमें धर्म को प्रथम स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि वही अर्थ और काम को मर्यादित करता है। यदि समाज से धर्म का नैतिक नियंत्रण समाप्त हो जाए, तो आर्थिक विकास भी स्वार्थ का माध्यम बन सकता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अराजकता में बदल सकती है। भारतीय दर्शन इसी संतुलन पर बल देता है।

विज्ञान और अध्यात्म – विरोध नहीं, समन्वय: भारतीय परंपरा आधुनिक विज्ञान का विरोध नहीं करती, बल्कि ज्ञान के व्यापक स्वरूप को स्वीकार करती है। आधुनिक विज्ञान मुख्यत: भौतिक जगत की व्याख्या करता है, जबकि भारतीय दर्शन चेतना, प्रकृति और ब्रह्मांड के आध्यात्मिक आयामों पर भी विचार करता है। उपनिषदों और भगवद्गीता का संदेश है कि भौतिक प्रगति आवश्यक है, किंतु उसके साथ आत्मबोध और नैतिकता का संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान और अध्यात्म को परस्पर पूरक माना गया है।

भारतीय आख्यानों को उनके संदर्भ में समझने की आवश्यकता: भारतीय महाकाव्यों और पुराणों की अनेक कथाओं को केवल आधुनिक वैज्ञानिक कसौटी पर परखने से उनके सांस्कृतिक और दार्शनिक अर्थ छूट जाते हैं। परंपरागत आचार्यों ने इन प्रसंगों को प्रतीकात्मक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में समझाया है। भारतीय ज्ञान परंपरा का आग्रह है कि किसी भी ग्रंथ का मूल्यांकन उसकी अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि में किया जाए, न कि केवल आधुनिक पश्चिमी दृष्टिकोण से। आज भारत तीव्र वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और सांस्कृतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। परिवार व्यवस्था, सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान पर नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं। धर्मांतरण, सांस्कृतिक अस्मिता, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और सामाजिक समरसता जैसे विषय सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं। इन विषयों पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण हो सकते हैं, किंतु एक बात निर्विवाद है कि किसी भी राष्ट्र की दीर्घकालिक स्थिरता उसके सांस्कृतिक आत्मविश्वास, नैतिक मूल्यों और सामाजिक एकता पर निर्भर करती है।

धर्म का वास्तविक अर्थ – कर्तव्य और उत्तरदायित्व: भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ केवल मंदिर जाना या धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं है। माता–पिता की सेवा, सत्य का पालन, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, समाज के प्रति उत्तरदायित्व और दुर्बलों की रक्षा भी धर्म के ही स्वरूप हैं। महाराणा प्रताप का संघर्ष, राजा दिलीप का त्याग, आदि शंकराचार्य का राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक अभियान और भगवान श्रीराम का आदर्श शासन, इन सबमें धर्म जीवन–मूल्यों के रूप में प्रकट होता है, किसी संकीर्ण धार्मिक पहचान के रूप में नहीं। कुल निष्कर्ष रूप में कहें तो भारत में धर्म और राजनीति को कभी दो विरोधी संस्थाएं नहीं माना गया। भारतीय राजनीतिक दर्शन का मूल सिद्धांत यह रहा कि राजसत्ता धर्म अर्थात न्याय, मर्यादा और लोककल्याण के अधीन रहे। यही राजधर्म भारतीय राय–चिंतन की आत्मा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि धर्म और रिलीजन के बीच के अंतर को समझा जाए तथा भारतीय सभ्यता की अवधारणाओं का मूल्यांकन उसकी अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि में किया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय सांस्कृतिक दर्शन के बीच संतुलन स्थापित करके ही ऐसा समाज निर्मित किया जा सकता है, जो प्रगतिशील भी हो और अपनी सभ्यतागत जड़ों से जुड़ा भी रहे।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

ई–गवर्नेंस में उत्कृष्टता केवल राज्यों की राजधानियों या जिला मुख्यालयों तक सीमित नहीं रही

– **प्रो. एस. पी. सिंह बघेल**

कुछ क्षण केवल एक उपलब्धि भर नहीं होते, वे एक पूरी यात्रा को रोशन कर देते हैं। राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चार पंचायती राज पहलों का चयन ऐसा ही एक क्षण है, ऐसा क्षण जो किसी एक कार्यालय का नहीं, बल्कि हर ग्राम पंचायत और हर उस नागरिक का है, जिसने डिजिटल रूप से सशक्त ग्रामीण भारत के सपने पर भरोसा किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर, भारत की पंचायतें भरोसे, तकनीक और परिवर्तन का एक नया अध्याय लिख रही हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के बारह परिवर्तनकारी वर्षों के इस पड़ाव पर यह सम्मान विशेष महत्व रखता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार पंचायती राज संस्थाएं मात्र योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित निकायों से आगे बढ़कर, शासन की तीसरी स्तरीय व्यवस्था की आत्मविश्वासी, सक्षम और तकनीकी रूप से दक्ष संस्थाओं के रूप में स्थापित हुई हैं।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्कृष्ट लोक सेवा वितरण के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है।

इस वर्ष सात श्रेणियों में चयनित 17 परियोजनाओं में से 4 पंचायती राज क्षेत्र से संबंधित हैं, जो ज़मीनी स्तर पर नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु पिछले बारह वर्षों के निरंतर प्रयासों का स्वाभाविक परिणाम है।

ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु पंचायती राज मंत्रालय की प्रमुख पहल, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI), को डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक के आने से पहले, देश की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन केमूल्यांकन के लिए कोई मानकीकृत, डेटा आधारित राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध नहीं था। आज यह सूचकांक डेटा, प्रदर्शन, पहचान और जनभागीदारी को आपस में जोड़ने वाली एक पारदर्शी जवाबदेही व्यवस्था का निर्माण कर रहा है।

उल्लेखनीय यह है कि दो ग्राम पंचायतों ने अपने स्वयं के प्रयासों से यह सम्मान अर्जित किया है। महाराष्ट्र के सांगली जिले की कडे पुरग्राम पंचायत ने ग्रास रूट स्तर की पहलों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त कियाहै।

ये पुरस्कार मिलकर एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। ई–गवर्नेंस में उत्कृष्टता अब केवल राज्यों की राजधानियों या जिला मुख्यालयों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह समान रूप से हमारे गांवों और ग्राम सभाओं में भी स्थापित हो चुकी है। इस वर्ष 30 राज्यों की 1.65 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने इसमें भाग लिया, जो हमारे द्वारा मिलकर तैयार की गई संस्थागत क्षमता और विश्वास को दर्शाता है।

यह उपलब्धि संयोग से नहीं मिली है। पिछले बारह वर्षों में मंत्रालय ने पंचायतों को निरंतर बेहतर साधन उपलब्ध कराए हैं। ई–ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2.59 लाख से अधिक पंचायतों में योजना निर्माण, बजट और भुगतान प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ?3.16 लाख करोड़ से अधिक के ऑनलाइन लेन–देन संभव हुए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सभासार प्लेटफॉर्म, जो 23 भारतीय भाषाओं में कार्य करता है, अब 1.35 लाख से अधिक पंचायतों में चंद मिनटों में ग्राम सभा की कार्यवाही तैयार कर देता है। मेरी पंचायत ऐप, जिसे 1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है, विकास कार्यों की जानकारी सीधे नागरिकों तक पहुंचा रहा है।

इन प्रयासों के साथ–साथ, स्वामित्व योजना के तहत 3.30 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है तथा जून 2026 के मध्य तक 1.94 लाख गांवों के लिए 3.19 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों के संपत्ति अधिकार सुदृढ़ हुए हैं और उन्हें ऋण सुविधा प्राप्त करने में आसानी हुई है। पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2.82 लाख करोड़ की अनुदान राशि जारी की गई, जो अब तक की सर्वाधिक है। सोलहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2026 से 2031 के लिए ?4.35 लाख करोड़ की सिफारिश की है, जो लगभग 84 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने सेवा से समृद्धि– पंचायतों के नेतृत्व में सेवा वितरण विषय पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शुरू की है।

इन कार्यशालाओं में पंचायत प्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी और विषय विशेषज्ञ मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में लोगों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। इन कार्यशालाओं के माध्यम से सफल स्थानीय पहलों और नवाचारों को साझा किया जा रहा है, ताकि राज्य एक–दूसरे के अनुभवों से सीख सकें और अच्छे मॉडलों को व्यापक स्तर पर अपनाया जा सके। इनकी उपयोगिता और विस्तार की संभावनाएं बहुत व्यापक हैं। ह्द्ल 2026 में चयनित पंचायती राज संस्थाओं की उपलब्धियां देशभर की पंचायतों को प्रेरित कर रही हैं, और अनेक पंचायतें अपने गांवों में बेहतर सेवाएं पहुंचाकर समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ऐसे मॉडलों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सदैव यह बल देते रहे हैं कि सुशासन वही है जो नागरिकों का जीवन सरल बनाए। पारदर्शी और तकनीक सक्षम व्यवस्थाओं के माध्यम से प्राप्त ईज़ ऑफ़ लिविंग ही किसी सरकार की मंशा और क्षमता की सच्ची कसौटी है।

यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि दूसरों का सम्मान करना स्वयं के सम्मान का मार्ग प्रशस्त करता है। पंचायतों को डिजिटल साधनों से सशक्त बनाकर और उनकी क्षमता पर विश्वास जताकर, केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण मंच पर देश को सम्मानित होने का मार्ग प्रशस्त किया है।

जैसे–जैसे भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, सशक्त पंचायतों की भूमिका और भी केंद्रीय होती जा रही है। लगभग 90 करोड़ नागरिकों के ग्रामीण भारत में निवास करने के साथ, हमारी पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती ही हमारी सामूहिक प्रगति की गति तय करेगी। विकसित पंचायत, विकसित भारत से अलग नहीं, बल्कि उसकी सबसे मजबूत नींव है।

उल्लेखनीय यह है कि दो ग्राम पंचायतों ने अपने स्वयं के प्रयासों से यह सम्मान अर्जित किया है। महाराष्ट्र के सांगली जिले की कडे पुरग्राम पंचायत ने ग्रास रूट स्तर की पहलों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त कियाहै। ये पुरस्कार मिलकर एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। ई–गवर्नेंस में उत्कृष्टता अब केवल राज्यों की राजधानियों या जिला मुख्यालयों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह समान रूप से हमारे गांवों और ग्राम सभाओं में भी स्थापित हो चुकी है। इस वर्ष 30 राज्यों की 1.65 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने इसमें भाग लिया, जो हमारे द्वारा मिलकर तैयार की गई संस्थागत क्षमता और विश्वास को दर्शाता है।

ये चार राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार बेहतर प्रदर्शन, प्रगति और निरंतर आगे बढ़ने के प्रतीक हैं। ये जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे प्रत्येक सरपंच, पंचायत सचिव और महिला जनप्रतिनिधि के लिए एक प्रेरणा हैं कि उनके समर्पण और प्रयासों को पहचान मिल रही है, उनकी सराहना की जा रही है और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बारह वर्षों के निरंतर प्रयासों ने ही ऐसी उत्कृष्टता के उभरने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। ह्द्ल 2026 में मिली पहचान से लेकर देशभर में बढ़ती सेवा से समृद्धि कार्यशालाओं की गति तक, यह सफलता इस बात की पुष्टि करती है कि ग्रामीण भारत में ई–गवर्नेंस की जड़ें वास्तव में गहरी हो चुकी हैं, और विकसित पंचायत के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण की यह यात्रा हर गुजरते वर्ष के साथ और सशक्त होती जा रही है।

(लेखक केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री हैं।

जगन्नाथ रथयात्रा- उतार-चढ़ाव, विध्वंस और पुनर्निर्माण के बीच अमर है आस्था की परंपरा

रमेश शर्मा

पुरी की विश्वविख्यात भगवान जगन्नाथ रथयात्रा भारत की सांस्कृतिक एकता, सामाजिक समरसता और सनातन परंपरा की जीवंत अभिव्यक्ति है। इस वर्ष रथयात्रा शुरू हो गई है जोकि 24 जुलाई तक आयोजित होगी। 25 जुलाई को नीलाद्री बीजे के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मुख्य मंदिर में वापसी होगी तथा 27 जुलाई से पुन: दर्शन आरंभ होंगे। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस महापर्व में सहभागी बनते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि भारत की आध्यात्मिक चेतना समय, सत्ता और परिस्थितियों से कहीं अधिक शक्तिशाली है।

पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर चार धामों में से एक है तथा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन मठ का भी केंद्र है। मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण जगन्नाथ के रूप में अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को तीनों देवता भव्य रथों पर आरूढ़ होकर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करते हैं और कुछ दिनों बाद पुन: श्रीमंदिर लौटते हैं। भगवान जगन्नाथ नंदीघोष, बलभद्र तालध्वज और देवी सुभद्रा दर्पदलन रथ पर विराजते हैं। लाखों श्रद्धालु लगभग 50 मीटर लंबी रस्सियों से इन रथों को हाथों से खींचते हैं। रथ को खींचना ईश्वर की सेवा और पुण्य का कार्य माना जाता है। यही कारण है कि इस अवसर पर जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र की सभी सीमाएं स्वत: समाप्त हो जाती हैं।

पर्यावरण और लोककला का अद्भुत संदेश

रथयात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया से प्रारंभ होती है। प्रत्येक वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं और उनका निर्माण पूरी तरह पारंपरिक शिल्पकला से होता है। आधुनिक मशीनों के स्थान पर स्थानीय कारीगर अपनी पीढ़ियों से चली आ रही कला का उपयोग करते हैं। रथों के निर्माण में मुख्यत: काष्ठ का प्रयोग होता है और प्रकृति के संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह परंपरा भारतीय संस्कृति के उस विचार को पुष्ट करती है कि धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण एक–दूसरे के पूरक हैं। साथ ही यह स्थानीय शिल्पकारों और लोककला को जीवित रखने का भी प्रभावी माध्यम है।

सामाजिक समरसता का अनुपम उदाहरण

रथयात्रा का सबसे प्रेरक दृश्य वह होता है जब पुरी के गजपति महाराज स्वयं स्वर्ण झाड़ू से रथों के मार्ग की सफाई करते हैं। इस परंपरा को छेरा पहरा कहा जाता है। राजा के साथ राजपुरोहित तथा सबर जनजाति के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहते हैं। राजा द्वारा झाड़ू लगाना यह संदेश देता है कि ईश्वर के समक्ष कोई बड़ा या छोटा नहीं है। मंदिर की सेवा–व्यवस्था में भी विभिन्न समाजों और परंपराओं के लोगों की सहभागिता रहती है। यही कारण है कि जगन्नाथ धाम भारतीय सामाजिक समरसता और समावेशी संस्कृति का अद्वितीय प्रतीक माना जाता है।

पौराणिक कथा में छिपा सांस्कृतिक संदेश

मान्यता है कि यह क्षेत्र प्राचीनकाल में सबर जनजाति का था। उनके प्रमुख विश्ववसु भगवान नीलमाधव के उपासक थे। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने मंदिर निर्माण का आदेश दिया। बाद में समुद्र से प्राप्त दिव्य काष्ठ से भगवान की प्रतिमा बनाने का निर्देश मिला। स्वयं विश्वकर्मा बढ़ई के रूप में प्रतिमा निर्माण के लिए आए और अधूरी प्रतीत होने वाली उन्हीं प्रतिमाओं की स्थापना की गई। आज भी भगवान जगन्नाथ की विशिष्ट काष्ठ प्रतिमाएं उसी परंपरा का प्रतीक हैं।

भारत की सांस्कृतिक एकात्मता का प्रतीक

जगन्नाथ परंपरा भारत की सांस्कृतिक अखंडता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। भगवान श्रीकृष्ण का जन्म मथुरा में, कर्मभूमि द्वारका में और जगन्नाथ रूप में उनका प्रतिष्ठान पुरी में है। मान्यता है कि प्रथम काष्ठ समुद्र के माध्यम से द्वारका से पुरी पहुँचा। दूसरी ओर, देवी सुभद्रा का संबंध हस्तिनापुर से माना जाता है, जबकि विभीषण की आराधना से जुड़ी परंपरा दक्षिण की सांस्कृतिक स्मृतियों को जोड़ती है। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण– संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक चेतना इस एक मंदिर और रथयात्रा में समाहित दिखाई देती है। साथ ही भगवान अपने भाई और बहन के साथ विराजमान होकर भारतीय परिवार व्यवस्था और पारिवारिक समन्वय का भी संदेश देते हैं।

विध्वंस और पुनर्निर्माण का संघर्षपूर्ण इतिहास

जगन्नाथ मंदिर का इतिहास भक्ति के साथ ही संघर्ष और पुनर्जागरण का भी इतिहास है। 14वीं शताब्दी से लेकर मुगल काल तक मंदिर पर अनेक आक्रमण हुए। इलियास शाह, फिरोज शाह तुगलक, इस्माइल गाजी, अफगान आक्रमणकारी काला पहाड़ तथा बाद में कई मुगल सेनापतियों ने मंदिर को क्षति पहुँचाई। सबसे भीषण आक्रमण 1568 में काला पहाड़ और बाद में औरंगज़ेब के शासनकाल में हुआ। अनेक बार मंदिर को ध्वस्त किया गया, लूटपाट हुई और श्रद्धालुओं का नरसंहार भी हुआ। किंतु हर संकट के समय पुजारियों और भक्तों ने भगवान की प्रतिमाओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाकर परंपरा को जीवित रखा। यही कारण है कि मंदिर का इतिहास विध्वंस से अधिक पुनर्निर्माण और अटूट आस्था का इतिहास बन गया। मुगल सत्ता के पतन के बाद मराठा शासनकाल में मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य गति पकड़ता है। आगे चलकर इंदौर की धर्मपरायण महारानी अहिल्याबाई होल्कर सहित अनेक शासकों और श्रद्धालुओं के प्रयासों से मंदिर को पुन: उसका गौरव प्राप्त हुआ।

आज भी उतना ही प्रासंगिक है यह संदेश

आज जब समाज अनेक प्रकार की विभाजक प्रवृत्तियों का सामना कर रहा है, तब जगन्नाथ रथयात्रा हमें समरसता, सेवा, समानता और राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश देती है। लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के एक ही रस्सी को पकड़कर भगवान के रथ को आगे बढ़ाते हैं। यही दृश्य भारतीय संस्कृति के उस आदर्श को साकार करता है, जिसमें समूचा समाज एक परिवार माना गया है, इसीलिए जगन्नाथ रथयात्रा केवल ओडिशा का पर्व नहीं, बल्कि भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता और अजेय आस्था का महापर्व है। सदियों तक आक्रमण, विध्वंस और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी यह परंपरा आज उसी श्रद्धा, वैभव और उत्साह के साथ जीवित है। यही इसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि और भारत की सांस्कृतिक शक्ति का सबसे सशक्त प्रमाण है।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं।)

जापान ओपनः भारत का मेंस सिंगल्स अभियान समाप्त, विमेंस सिंगल्स में उन्नति की हार

एजेंसी
टोक्यो। 'जापान ओपन 2026' के मेंस सिंगल्स ड्रॉ में भारत की उम्मीदें खत्म हो गईं। 'बीडब्ल्यूएफ सुपर 750' टूर्नामेंट के शुरुआती दौर के मुकाबलों में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी दोनों बाहर हो गए, जबकि उन्नति हुड्डा भी विमेंस सिंगल्स प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। वर्ल्ड नंबर 14 खिलाड़ी लक्ष्य सेन टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम में घरेलू खिलाड़ी कोकी वातानाबे का सामना नहीं कर सके। वातानाबे ने यह मुकाबला 21-16, 21-14 से अपने नाम किया। भारतीय खिलाड़ी शुरुआत से ही पिछड़ते नजर आए। वातानाबे ने दोनों सेट में मिड-गेम इंटरवल पर बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। वापसी की कोशिश के बावजूद, लक्ष्य मैच का रुख नहीं बदल सके और जापानी शटलर ने सिर्फ 38 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह वातानाबे की भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ सात मुकाबलों में तीसरी जीत रही। दूसरी तरफ, आयुष शेट्टी टूर्नामेंट में बने रहने के काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन आखिरकार तीन गेम के कड़े मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी कुनलावुत विटिडसर्न से हार का सामना करना पड़ा। थाई स्टार ने कड़े मुकाबले वाले पहले गेम को 21-19 से अपने नाम किया, जिसमें उन्होंने सेट के ज्यादातर समय मामूली बढ़त बनाए रखी। आयुष ने दूसरे गेम में शानदार वापसी की।

एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप - अवेयरनेस रैली के पोस्टर का विमोचन

जयपुर। राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित की जा रही तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 18 जुलाई को होने वाली अवेयरनेस रैली के पोस्टर का विमोचन राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बी.एल. सोनी ने किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों को खेलों के माध्यम से आगे बढ़ाने और समाज में समावेशिता का संदेश देने के लिए ऐसे आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में रैली से जुड़ने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर वर्ल्ड थ्रो बॉल फेडरेशन की अध्यक्ष निर्मला रावत, राजस्थान पैरा थ्रोबाल एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजराज शेखावत, पदाधिकारी हिरल राठौड़, सुशीला एवं अन्य सहयोगी उपस्थित रहे। सभी ने आगामी आयोजन की तैयारियों पर चर्चा करते हुए इसे सफल बनाने का संकल्प लिया। आयोजकों ने बताया कि 18 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली का उद्देश्य पैरा थ्रोबॉल खेल के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, दिव्यांग खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना तथा समाज में समावेशिता (Inclusion), सशक्तिकरण (Empowerment) और उत्कृष्टता (E&cellence) का संदेश देना है।

मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हुए बेल्जियम के मिडफील्डर यूरी टिलेमैन्स, 2031 तक का हुआ करार

मैनचेस्टर। प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बेल्जियम के अनुभवी मिडफील्डर यूरी टिलेमैन्स को जून 2031 तक के लिए साइन करने की पुष्टि की है। हालांकि, यह ट्रांसफर सभी जरूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधिकारिक रूप से लागू होगा। टिलेमैन्स 2026/27 सीजन से पहले माइकल कैरिक की टीम से जुड़ेंगे। यूनाइटेड में वह प्रतिष्ठित नंबर 18 की जर्सी पहनेंगे। यह वही जर्सी है जिसे क्लब के महान मिडफील्डर पॉल स्कोल्स ने 1996/97 सीजन से लेकर 2010/11 में अपने रिटायरमेंट तक पहना था। 27 वर्षीय टिलेमैन्स बेल्जियम के लिए 90 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। वह हाल ही में फीफा विश्व कप खेलकर लौटे हैं, जहां उन्होंने अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। क्लब से जुड़ने के बाद टिलेमैन्स ने कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी बड़ी टीम का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, 'शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि मैं कितना खुश हूं। इतने बड़े और ऐतिहासिक क्लब के लिए खेलना मेरे बचपन के सपनों में शामिल था। यह मेरी वर्षों की मेहनत का नतीजा है।'

टेन डोशेट बना रहे भारतीय कोचिंग सेटअप छोड़ने की योजना, गंभीर की मंजूरी का इंतजारः रिपोर्ट

नई दिल्ली। भारत के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट इंग्लैंड दौरे के बाद टीम का साथ छोड़ने की योजना बना रहे हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ 19 जुलाई को होने वाला तीसरा वनडे मैच उनका आखिरी असाइनमेंट हो सकता है। 'क्रिकबज' की रिपोर्ट के मुताबिक, नीदरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को अपनी इच्छा के बारे में बता दिया है। हालांकि, आखिरी फैसला हेड कोच गौतम गंभीर लेंगे, जिन्होंने डोशेट को भारतीय टीम में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय टीम ने इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शर्मनाक प्रदर्शन किया था। हालांकि, यह प्रदर्शन रयान टेन डोशेट के जाने की वजह नहीं है, क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, टेन डोशेट पूरी तरह से निजी कारणों से आगे बढ़ना चाहते हैं। डोशेट के तीन बेटे अभी काफी छोटे हैं। उनकी पत्नी नौकरीपेशा हैं। ऐसे में डोशेट लंदन में रहने वाले अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। टीम इंडिया के साथ काम करने में डोशेट को बहुत ज्यादा यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए माना जा रहा है कि टेन डोशेट ऐसी भूमिका की तलाश में हैं जिसमें कम यात्रा करनी पड़े और वे अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकें।

वर्ल्ड रिकॉर्डधारी शूटर अभिनव साव को बंगाल सरकार ने किया सम्मानित

एजेंसी
कोलकाता। जर्मनी के सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचने वाले आसनसोल के युवा शूटर अभिनव साव को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सम्मानित किया गया है। राज्य के खेल मंत्री डॉ. इंद्रनील खां ने कोलकाता स्थित न्यू सेक्रेटेरिएट कार्यालय में उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर अभिनव के माता-पिता भी मौजूद रहे। सम्मान समारोह में मंत्री डॉ. खां ने अभिनव की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि अभिनव बंगाल ही नहीं, पूरे देश का गौरव हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार अभिनव के ओलंपिक पदक जीतने के लक्ष्य

को पूरा करने के लिए हरसंभव सहयोग करेगी।

अभिनव साव ने जर्मनी के सुहल में आयोजित 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में अपनी जोड़ीदार सांभवी के साथ 505.8 अंक हासिल कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले इस स्पर्धा का विश्व रिकॉर्ड 499.9 अंक था। शूटिंग जैसे अत्यंत प्रतिस्पर्धी खेल में लगभग छह अंकों के अंतर से रिकॉर्ड तोड़ना बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह अभिनव का 17वां अंतरराष्ट्रीय पदक है। वह वर्ष 2022 से भारतीय शूटिंग टीम का हिस्सा हैं। महज 10 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन बनने वाले अभिनव ने 14 वर्ष की आयु में जर्मनी के सुहल में ही अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। इसके बाद से वह जूनियर विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप में लगातार देश के लिए पदक जीतते आ रहे हैं। वर्ष 2025 में कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री की ओर से भी बधाई मिली थी। सम्मान समारोह के दौरान अभिनव साव ने मंत्री डॉ. इंद्रनील खां का आभार व्यक्त किया। मंत्री ने कहा कि अभिनव जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं और उनका विश्व रिकॉर्ड भारतीय खेल जगत के लिए गर्व का विषय है।

नोएडा किंग्स टीम का ट्रायल 17 जुलाई को नोएडा में, मुरादाबाद से भी जाएंगे खिलाड़ी

एजेंसी
मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश क्रिकेट टी-20 लीग के चौथे सीजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर नोएडा किंग्स टीम ने ट्रायल की तिथियों की घोषणा कर दी है। टीम की ओर से 17 जुलाई को नोएडा स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन मुरादाबाद के सचिव व पूर्व रणजी खिलाड़ी विजय गुप्ता ने बताया कि इन ट्रायल्स में मुरादाबाद से भी बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। जिले के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी पंजीकरण करा चुके हैं और चयन में जगह बनाने को उत्साहित हैं। उन्होंने आगे बताया कि यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन का आगाज 14 अगस्त से होगा। इसमें मेरठ मेवरिक्स, गोरखपुर लायंस, काशी रुद्रास, नोएडा किंग्स, कानपुर सुपरस्टार और लखनऊ फाल्कंस टीमें प्रतिभाग करेंगी। अधिकांश टीमों के ट्रायल लगभग पूरे हो चुके हैं। अब नोएडा किंग्स ने भी अपनी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक खिलाड़ी 16 जुलाई तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

आईसीसी वनडे रैंकिंगः अक्षर पटेल ऑलराउंडरों की टॉप-10 सूची में शामिल

एजेंसी
नई दिल्ली। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन का इनाम भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल को आईसीसी वनडे रैंकिंग में मिला है। ताजा रैंकिंग में अक्षर तीन स्थान की छलांग लगाकर ऑलराउंडरों की सूची में नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं। बर्मिंघम में खेले गए पहले वनडे में अक्षर ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने चार विकेट लेने के साथ-साथ 52 गेंदों में 57 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर भारत को छह विकेट से जीत में अहम भूमिका निभाई थी।इस प्रदर्शन के दम पर अक्षर बल्लेबाजों की रैंकिंग में 18 स्थान की छलांग लगाकर 73वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं गेंदबाजों की सूची में भी वह दो स्थान ऊपर चढ़कर 42वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

बल्लेबाजी करते हुए 75 गेंदों में 80 रन बनाए। इस पारी के बाद उन्हें रैंकिंग में 12 रेटिंग अंक का फायदा हुआ है। अब गिल और वनडे के नंबर-1 बल्लेबाज डैरिल मिचेल के बीच सिर्फ 11 रेटिंग अंकों का अंतर

रह गया है। लंबे समय बाद वनडे टीम में लौटे जसप्रीत बुमराह ने एक विकेट हासिल किया और गेंदबाजों की रैंकिंग में 24वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 52 रन की उपयोगी पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजों की रैंकिंग में उन्होंने 24 स्थान की छलांग लगाकर 177वां स्थान हासिल किया। ऑलराउंडरों की सूची में भी वह 16 स्थान ऊपर चढ़कर 55वें नंबर पर पहुंच गए हैं इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने 76 गेंदों में 76 रन की पारी खेली, जिसके बाद वह वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में संयुक्त रूप से 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा लियाम डॉसन ने 68 रन की जुझारू पारी खेली, जिससे उन्हें बल्लेबाजों की रैंकिंग में 81 स्थान का फायदा हुआ और अब वह 262वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

शुभमन गिल नंबर-1 बनने के करीब

वनडे टीम में वापसी करने वाले शुभमन गिल ने पहले मैच में शानदार

स्पेन से हार के बाद टूटे एमबाप्पे ने कहा, हमने विश्वकप सेमीफाइनल जैसा खेल नहीं खेला

एजेंसी
आर्लिंग्टन। फीफा विश्वकप 2026 के सेमीफाइनल में स्पेन से 0-2 की हार के बाद फ्रांस के कप्तान किलियन एमबाप्पे ने कहा कि उनकी टीम ने वैसा प्रदर्शन ही नहीं किया, जैसा विश्वकप के सेमीफाइनल में होना चाहिए था। उन्होंने माना कि फ्रांस रणनीतिक, तकनीकी और समग्र प्रदर्शन के स्तर पर स्पेन से काफी पीछे रहा।

पूरे टूर्नामेंट में आठ गोल कर शानदार फॉर्म में रहे एमबाप्पे अपनी टीम को लगातार तीसरे विश्वकप फाइनल में नहीं पहुंचा सके। स्पेन ने एटीएंडटी स्टेडियम में फ्रांस को हराकर उसका खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया।

मैच के बाद एमबाप्पे ने फ्रेंच ब्रॉडकास्टर एम6 से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमने वैसा मैच खेला, जैसा हम खेलना चाहते थे। चाहे रणनीति की बात हो, तकनीकी स्तर की या हमारे पूरे प्रदर्शन की, हम हर मोर्चे पर पीछे रहे।

उन्होंने कहा, जब आप विश्वकप के सेमीफाइनल में वह नहीं करते, जो करना चाहिए तो आप जीत नहीं सकते। एमबाप्पे ने बताया कि फ्रांस की योजना स्पेन पर आगे से दबाव बनाकर उसे अपने खेल की लय में आने से रोकने की थी। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य था कि हम स्पेन पर आगे से दबाव बनाएं ताकि वह अपने धीमे और नियंत्रित खेल में न आ सके। क्योंकि खेल को नियंत्रित करने में वे हमसे बेहतर हैं लेकिन हम इसमें पूरी तरह असफल रहे।

एमबाप्पे ने हार का सबसे बड़ा कारण मिडफील्ड की कमजोरी को बताया। उन्होंने कहा, हम बार-बार मिडफील्ड में 3 बनाम 2 की स्थिति में फंसते रहे। स्पेन जैसी टीम के खिलाफ यह बहुत बड़ी समस्या है। जब ऐसी कई गलतियां एक साथ होती हैं तो नतीजा हार ही होता है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी निराशा है।फ्रांस के कप्तान ने कहा कि टीम का सपना फाइनल में पहुंच कर देश को फिर से विश्व चैंपियन बनाने का था। उन्होंने कहा, हमारा सपना था कि हम फाइनल में पहुंचें, अपने देश को फिर से सपने देखने का मौका दें और इतिहास रचें लेकिन अब हमें इस हार का सामना सिर ऊंचा रखकर करना होगा। उन्होंने आगे कहा, मेरा मानना है कि जब आप जीतते हैं तो सिर ऊंचा रखकर जीतते हैं और जब हारते हैं तो सिर ऊंचा रखकर हार स्वीकार करनी चाहिए।

एमबाप्पे ने स्वीकार किया कि पूरी टीम इस हार से बेहद निराश है। उन्होंने कहा, इस समय मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि मैं और पूरी टीम कितनी निराश है। लेकिन हमें खुद को संभालना होगा, छुट्टियों पर जाना होगा और फिर नई शुरुआत करनी होगी। क्योंकि फुटबॉल किसी का इंतजार नहीं करता। हमें इस असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा।

ओरिएंटल कप 2026: ग्रैंड फिनाले के लिए मंच तैयार, दोनों वर्गों में मिलेंगे नए चैंपियन

एजेंसी
नई दिल्ली। ओरिएंटल कप 2026 के चौथे संस्करण का बहुप्रतिक्षित ग्रैंड फिनाले अब पूरी तरह तैयार है। डॉ. अंबेडकर स्टेडियम में खेले गए सातवें दिन के मुकाबलों में लड़कों और लड़कियों के सेमीफाइनल आयोजित किए गए, जहां फाइनल में जगह बनाने के लिए टीमों के बीच रोमांचक संघर्ष देखने को मिला।

पूरे दिन उच्च स्तर की फुटबॉल, कड़े मुकाबले और खिलाड़ियों के शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन देखने को मिले, जिसमें मॉडर्न स्कूल की ध्वनि विदाद का शानदार हैट्रिक आकर्षण का केंद्र रही।

लड़कियों के वर्ग में मॉडर्न स्कूल और भारती पब्लिक स्कूल ने फाइनल में जगह बनाई, जबकि लड़कों के वर्ग में स्टेप बाय स्टेप स्कूल, नोएडा और जी.डी. गोयनका स्कूल, द्वारका ने जीत दर्ज कर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार चारों फाइनलिस्ट टीमें खिताबी मुकाबले में पहुंची हैं, जिससे यह तय हो गया है कि चौथे संस्करण में लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों को नए चैंपियन मिलेंगे। गुरुवार, 16 जुलाई को डॉ. अंबेडकर स्टेडियम में होने वाले ग्रैंड फिनाले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और कोच सरदार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। दिन के पहले मुकाबले में लड़कियों के पहले सेमीफाइनल में भारती पब्लिक स्कूल ने स्टेप बाय स्टेप स्कूल, नोएडा को 4-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। यशिका ने 11वें और 15वें मिनट में दो गोल कर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, जबकि नितिका ने 19वें और 27वें मिनट में दो और गोल जोड़कर जीत सुनिश्चित की। दोनों हाफ में दो-दो गोल करते हुए भारती पब्लिक स्कूल ने एकतरफा अंदाज में खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। पहले लड़कों के सेमीफाइनल में स्टेप बाय स्टेप स्कूल, नोएडा ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसंत विहार को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दोनों टीमों ने पूरे मैच के दौरान कई गोल करने के मौके बनाए और रक्षात्मक खेल में भी मजबूती दिखाई। मुकाबले का एकमात्र और निर्णायक गोल 21वें मिनट में वंश गुलाटी ने किया, जिसकी बदौलत स्टेप बाय स्टेप स्कूल पहली बार ओरिएंटल कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे लड़कों के सेमीफाइनल में दिन का सबसे रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां जी.डी. गोयनका स्कूल, द्वारका ने मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली को पेनल्टी शूटआउट में हराकर फाइनल में जगह बनाई। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कोई गोल नहीं हुआ। 30वें मिनट में ध्रुव तुली ने मदर्स इंटरनेशनल स्कूल को बढ़त दिलाई लेकिन छह मिनट बाद आयान नाइक ने शानदार गोल कर जी.डी. गोयनका की बराबरी करा दी। निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 रहने के बाद मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें जी.डी. गोयनका ने 5-4 से जीत दर्ज करते हुए कुल 6-5 के अंतर से फाइनल का टिकट हासिल किया। दिन के अंतिम मुकाबले और दूसरे लड़कियों के सेमीफाइनल में मॉडर्न स्कूल ने वसंत वैली स्कूल को 4-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

ध्वनि विदाद ने शानदार हैट्रिक लगाते हुए 12वें, 35वें और 36वें मिनट में गोल किए, जबकि कीर्ति पांचाल ने 23वें मिनट में एक गोल दागा। पूरे मुकाबले में मॉडर्न स्कूल का दबदबा बना रहा और टीम ने शानदार प्रदर्शन के दम पर आसानी से फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

महिला मुख्य आरक्षी पुष्पा चाहर व रमा यादव ने खेल में जीते स्वर्ण व रजत पदक

एजेंसी
मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की पुलिस में पदस्थ महिला मुख्य आरक्षी पुष्पा चाहर को पावर लिफ्टिंग में रजत पदक और रमा यादव को टेबल टेनिस में 6 स्वर्ण पदक और बैडमिंटन डबल्स में दो रजत पदक प्राप्त होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों ने सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया। मुरादाबाद में तैनात महिला मुख्य आरक्षी पुष्पा चाहर ने करनाल (हरियाणा) में आयोजित ऑल इंडिया भारोत्तोलन क्लस्टर की पावर लिफ्टिंग (69 किलोग्राम वर्ग) प्रतियोगिता में रजत पदक (सिल्वर मेडल) प्राप्त किया है। वहीं महिला मुख्य आरक्षी रमा यादव ने जनपद रामपुर में आयोजित अन्तरजनपदीय बैडमिंटन क्लस्टर के अंतर्गत महिला वर्ग टेबल टेनिस ऑल ओवर चैंपियनशिप में 06 स्वर्ण पदक तथा बैडमिंटन डबल्स प्रतियोगिता में 02 रजत पदक प्राप्त किये हैं।

इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिम पुलिस

अधीक्षक देहात कुंवर आकाश सिंह पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह एसपी ट्रैफिक व क्षेत्राधिकारी सुभाष चंद गंगवार ने महिला मुख्य आरक्षी पुष्पा चाहर और महिला मुख्य आरक्षी रमा यादव को उनकी उत्कृष्ट खेल उपलब्धियां पर सम्मानित कर उनका उत्साह वर्धन किया।

वार्षिक बैठक में आईसीसी बोर्ड के बड़े फैसले, मॉरीशस बना 111वां सदस्य

एजेंसी
एडिनबर्ग। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) बोर्ड ने अपनी वार्षिक बैठक में प्रशासन, सदस्यता और सदस्य देशों को समर्थन से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। बैठक में क्रिकेट के वैश्विक विस्तार और सदस्य देशों के बेहतर संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आईसीसी बोर्ड ने दो नई उप-समितियों के गठन को मंजूरी दी।

गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया करेंगे। इस समिति में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के डॉ. मोहम्मद मूसाजी और आईसीसी की स्वतंत्र निदेशक डॉ. रोज़ रिवाज़ भी शामिल हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइजी लीग्स कमेटी का भी गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश क्रिकेट

बोर्ड के तमीम इकबाल करेंगे। समिति में क्रिकेट नामीबिया के डॉ. रूडी वान वूरन, देवजीत सैकिया, इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के रिचर्ड गोल्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के टॉड ग्रीनबर्ग शामिल हैं। आईसीसी ने मॉरीशस को अपना 111वां सदस्य देश बनाने की मंजूरी दे दी है। परिषद ने कहा कि यह फैसला दुनिया भर में क्रिकेट के विस्तार और नए देशों में खेल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईसीसी बोर्ड ने क्रिकेट वेस्टइंडीज को सहायता प्रदान करने के लिए 1 करोड़ 28 लाख 20 हजार अमेरिकी डॉलर (12.82 मिलियन डॉलर) के ऋण को मंजूरी दी है। आईसीसी बोर्ड ने क्रिकेट कनाडा की सदस्यता बहाल करने के लिए आवश्यक शर्तों को मंजूरी दी है। हालांकि, जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक क्रिकेट कनाडा का निलंबन जारी रहेगा।

श्रीलंका क्रिकेट पर भी चर्चा

आईसीसी बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट के नए संविधान की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। बोर्ड ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की आवश्यकता दोहराई। तब तक श्रीलंका क्रिकेट को आईसीसी बोर्ड की बैठकों में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिलेगा।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिली मान्यता

आईसीसी बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को पूर्ण सदस्य निदेशक (फुल मेंबर डायरेक्टर) के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है।

फ्रांस क्रिकेट को चेतावनी

आईसीसी की वार्षिक आम बैठक में फ्रांस क्रिकेट को सदस्यता मानदंडों के उल्लंघन के कारण औपचारिक चेतावनी (ऑन नोटिस) पर रखने का फैसला किया गया।

राही सरनोबत ने कहा- भारतीय टीम में जगह बनाना आसान नहीं, अब वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स पर नजर

एजेंसी
नई दिल्ली। भारत की स्टार पिस्टल निशानेबाज और एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता राही सरनोबत ने कहा है कि मौजूदा समय में भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। उन्होंने कहा कि घरेलू चयन ट्रायल इतने प्रतिस्पर्धी हो चुके हैं कि हर खिलाड़ी को हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ता है। हाल ही में महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा के टी-4 राष्ट्रीय चयन ट्रायल में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली राही अब चीन में होने वाले ट्रूस्स्या विश्व कप और एशियन गेम्स की तैयारियों में जुटी हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान उन्होंने कहा कि चयन ट्रायल में दबाव के बीच अपनी प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। राही ने कहा, राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना कभी आसान नहीं होता, क्योंकि भारत के घरेलू ट्रायल बेहद प्रतिस्पर्धी हैं। स्कोर से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने दबाव में भी अपनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किया। इससे विश्वास मिला कि पिछले कुछ महीनों की मेहनत सही दिशा में जा रही है। अब लक्ष्य इसी निरंतरता को बनाए रखना है। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी

राही ने भारतीय महिला 25 मीटर पिस्टल टीम को अनुभव और युवा प्रतिभा का बेहतरीन मिश्रण बताया। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी टीम में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आते हैं, जबकि अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव बड़े मुकाबलों के दबाव को संभालने में मदद करता है। उन्होंने कहा, हर पीढ़ी टीम में कुछ नया लेकर आती है। युवा खिलाड़ियों का उत्साह और निडर सोच टीम को मजबूत बनाती है, जबकि अनुभव कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना सिखाता है। इतनी प्रतिभाशाली टीम का हिस्सा होना गर्व की बात है। राही ने माना कि भारत में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का प्रतिस्पर्धी स्तर दुनिया के सबसे कठिन स्तरों में शामिल है। उन्होंने कहा कि मनु भाकर और ईशा सिंह जैसी विश्वस्तरीय निशानेबाजों के साथ रोजाना अभ्यास करने से सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होता है। उन्होंने कहा, भारत में प्रतिस्पर्धा का स्तर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप मनु और ईशा जैसी खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करते हैं तो हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ता है। इससे सभी खिलाड़ी लगातार बेहतर होते हैं और एक-दूसरे के प्रति सम्मान भी बना रहता है।

जापान में पंजाब एफसी, बेंगलुरु एफसी की शानदार जीत, एफसी गोवा को मिली हार

एजेंसी
कुराते। भारतीय फुटबॉल के लिए मंगलवार का दिन रोमांचक रहा। देश की टॉप डेवलपमेंटल टीमों का मुकाबला जापान की जे-लीग टीमों से हुआ। इस दौरान कहीं दबदबा देखने को मिला तो कहीं रोमांचक मुकाबले हुए। कुल मिलाकर दिन भारतीय टीमों के नाम रहा। पंजाब एफसी और बेंगलुरु एफसी ने दो मैच जीते, जबकि एफसी गोवा को करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। दिन के सबसे शानदार प्रदर्शन में, पंजाब एफसी ने अविस्पा फुकुओका को 5-0 से करारी शिकस्त दी। पंजाब की टीम ने मैच की शुरुआत से ही जबरदस्त खेल दिखाया। सिंगमायुम शमी ने शुरुआती दौर में ही दो गोल (तीसरे और 28वें मिनट में) करके टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। ओमांग डोडम (42वें मिनट) और नगारिन शाइजा (55वें मिनट) ने बढ़त को और बढ़ाया, और आखिर में विशाल यादव ने स्टॉपेज टाइम (90+2 मिनट) में गोल करके जीत पर मुहर लगा दी। बेंगलुरु एफसी ने जबरदस्त जज्बा दिखाते हुए गिरावांज किताक्युशु के खिलाफ 3-2 से मुश्किल जीत हासिल की। ??र्युनोसुके इमाई के 40वें मिनट के गोल से पिछड़ने के बाद, बेंगलुरु ने दूसरे हाफ में वापसी की। रक्षित प्रिया अनिल ने 61वें मिनट में बराबरी का गोल किया।

आईसीसी ने बदले विश्व कप और टी-20 विश्व कप के प्रारूप, मुकाबले होंगे और रोमांचक

एजेंसी
एडिनबर्ग। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अपने प्रमुख पुरुष टूर्नामेंटों के प्रारूप में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है। आईसीसी बोर्ड की वार्षिक बैठक में पुरुष क्रिकेट विश्व कप और टी-20 विश्व कप के नए प्रारूप को स्वीकृति मिली। परिषद का उद्देश्य टूर्नामेंटों को अधिक प्रतिस्पर्धी, रोमांचक और हर मैच को अधिक महत्वपूर्ण बनाना है।

इसके साथ ही आईसीसी ने वर्ष 2028 के पुरुष टी-20 विश्व कप की नई क्वालीफिकेशन प्रणाली को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा सहयोगी (एसोसिएट) देशों के लिए 16 टीमों वाले एक नए वैश्विक टूर्नामेंट का भी प्रस्ताव रखा गया है।

आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में अब भी 14 टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन टूर्नामेंट का प्रारूप पूरी तरह बदल दिया गया है। नए प्रारूप में प्रतियोगिता तीन चरणों में खेली जाएगी। पहले चरण में निचली रैंकिंग की तीन टीमें सुपर सीरीज खेलेंगी, जिसमें शीर्ष टीम अगले दौर में पहुंचेगी। दूसरे चरण में दो समूहों में छह-छह टीमें होंगी। इसके बाद सुपर-7 चरण खेला जाएगा, जिसमें सात टीमें राउंड-रॉबिन मुकाबले खेलेंगी। सुपर-7 की शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आईसीसी का मानना है कि इस बदलाव से शुरुआती मुकाबलों का महत्व बढ़ेगा और हर चरण में प्रतिस्पर्धा अधिक कड़ी होगी।

टी-20 विश्व कप में अब सुपर-10 और एलिमिनेटर मुकाबले

पुरुष टी-20 विश्व कप में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब 20 टीमें पांच समूहों में विभाजित होंगी, जिनमें प्रत्येक समूह में चार-चार टीमें रहेंगी। हर समूह से दो टीमें अगले चरण में पहुंचेंगी। इसके बाद सुपर-10 चरण खेला जाएगा, जिसमें दो समूहों में पांच-पांच टीमें होंगी। प्रत्येक समूह की शीर्ष टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर मुकाबले खेलेंगी। एलिमिनेटर के विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। आईसीसी का कहना है कि एलिमिनेटर की शुरुआत से सुपर-10 चरण के अंतिम मुकाबलों तक रोमांच और प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी।

2028 टी-20 विश्व कप के लिए नई क्वालीफिकेशन प्रणाली

आईसीसी ने 2028 टी-20 विश्व कप के लिए नई क्वालीफिकेशन प्रणाली भी तय कर दी है। स्कॉटलैंड सीधे यूरोप रीजनल फाइनल में पहुंचेगा। 2026 टी-20 विश्व कप खेलने वाली लेकिन सीधे क्वालीफाई नहीं करने वाली टीमें ग्लोबल क्वालीफायर में उतरेंगी। ग्लोबल क्वालीफायर में क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं से आठ अन्य टीमें भी शामिल होंगी।अफ्रीका, एशिया और यूरोप से दो-दो टीमें, जबकि अमेरिका और ईस्ट एशिया-प्रशांत क्षेत्र से एक-एक टीम क्वालीफाई करेंगी। ग्लोबल क्वालीफायर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीमें टी-20 विश्व कप 2028 में जगह बनाएंगी।

आईसीसी बोर्ड ने एसोसिएट सदस्य देशों के लिए 16 टीमों वाले नए वैश्विक टूर्नामेंट के प्रस्ताव को भी समर्थन दिया है। यह प्रतियोगिता टी-20 विश्व कप से पहले आयोजित की जाएगी, जिससे उभरती क्रिकेट टीमों को अधिक अंतरराष्ट्रीय मुकाबले और उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा। हालांकि, इस नए टूर्नामेंट को अंतिम मंजूरी नवंबर में होने वाली आईसीसी की वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति की समीक्षा के बाद दी जाएगी। आईसीसी का मानना है कि इन बदलावों से विश्व क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ेगा, उभरती टीमों को अधिक अवसर मिलेंगे और दर्शकों को पहले मैच से लेकर फाइनल तक लगातार रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।

रुपया और कमजोर हुआ, 96.25 प्रति डॉलर पर बंद

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग आने से रुपया नौ पैसे टूट गया और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 96.25 रुपये का बोला गया। पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा 48 पैसे गिरकर 96.16 रुपये प्रति डॉलर पर रही थी। रुपये की शुरुआत आज 13 पैसे की बढ़त में 96.12 रुपये प्रति डॉलर पर हुई। कुछ ही देर बाद यह 96.05 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हो गया। हालांकि इसके बाद डॉलर की मांग आने से दोपहर बाद तक यह 96.35 रुपये प्रति डॉलर तक टूट गया था। अंत में 96.25 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में आज हल्की तेजी रही। यह अब भी 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। कारोबारियों ने बताया कि बाजार में बाद में डॉलर की मांग निकलने से भारतीय मुद्रा दबाव में आ गयी। दुनिया की हालांकि अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक की नरमी ने इसे ज्यादा नहीं टूटने दिया।

ताइवान एक्सीलेंस ऑटोमेशन एक्सपो में प्रदर्शित की जायेंगी उन्नत औद्योगिक तकनीकें

मुंबई। मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में 22 जुलाई से आयोजित होने वाले चार दिवसीय ताइवान एक्सीलेंस ऑटोमेशन एक्सपो, 2026 में ताइवान की सबसे उन्नत औद्योगिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जायेगा, जिससे भारतीय विनिर्माताओं को भविष्य की बुद्धिमान (इंटेलिजेंट) विनिर्माण की झलक देखने का अवसर मिलेगा। यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार ऑटोमेशन एक्सपो 2026 में ताइवान एक्सीलेंस पवेलियन के अंतर्गत 22 पुरस्कार विजेता ताइवानी ब्रांड अपनी नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। इनमें एआई एज कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स एवं स्मार्ट ऑटोमेशन तथा औद्योगिक उपकरण एवं कंपोनेंट्स जैसे क्षेत्रों की अत्याधुनिक तकनीकें शामिल होंगी। इनका उद्देश्य भारतीय उद्योगों को उत्पादकता बढ़ाने, परिचालन क्षमता को मजबूत करने और अधिक टिकाऊ विनिर्माण व्यवस्था विकसित करने में सहायता प्रदान करना है। भारत का विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र तेजी से स्मार्ट फैक्ट्रियों और सतत (सस्टेनेबल) उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष की भागीदारी का प्रमुख आकर्षण 22 जुलाई को आयोजित 'ताइवान एक्सीलेंस प्रोडक्ट लॉन्च' होगा, जिसकी थीम है, ताइवान के एडैप्टिव सॉल्यूशंस के साथ सतत विनिर्माण का निर्माण। एचआईडब्ल्यूआईएन, आईबीएएसई, सिन्ट्रोन्स और सिन्टेक अपनी नवीनतम औद्योगिक तकनीकों का अनावरण करेंगे। वे यह भी प्रदर्शित करेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित और आत्मसाती तकनीकें किस प्रकार स्मार्ट एवं सतत विनिर्माण को नयी दिशा दे रही हैं। वर्ष 2025 में ताइवान के विनिर्माण उत्पादन ने नया रिकॉर्ड बनाया।

इंस्टामार्ट पर अब मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, जल्द शुरू होगी बेंगलुरु में ऑन-डिमांड डिलीवरी सेवा

नयी दिल्ली। कर्नाटक में बेंगलुरु के रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब यहां के गैस उपभोक्ताओं को क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट के जरिये एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। इसके लिए इंस्टामार्ट ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (एचपीसीएल) से हाथ मिलाया है और ऑन-डिमांड डिलीवरी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि देश में पहली बार किसी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एलपीजी सिलेंडर की ऑन-डिमांड डिलीवरी सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत उपभोक्ता अब इंस्टामार्ट के माध्यम से एचपीसीएल का 10 किलोग्राम 'एचपी नव्या' कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर मंगवा सकेंगे। कंपनी ने बताया कि एचपी नव्या एक हल्का, जंग-रोधी और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर है। इसकी पारदर्शी बॉडी के कारण उपभोक्ता आसानी से गैस का स्तर देख सकते हैं। इसका ठोस डिजाइन इसे अपार्टमेंट, छोटे परिवारों, छात्रों, कामकाजी पेशेवरों तथा अतिरिक्त एलपीजी सिलेंडर की आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त बनाता है। कंपनी ने बताया कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं के पास पहले से घरेलू एलपीजी कनेक्शन होना जरूरी नहीं होगा। इससे छात्र अविवाहित कामकाजी लोग और छोटे परिवार भी आसानी से इस सेवा का उपयोग कर सकेंगे।

EPFO वेतन सीमा बढ़ाने का फैसला फिलहाल टला, 15,000 रुपये की पुरानी सीमा पर ही बनी रहेगी अनिवार्य पीएफ कटौती

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य वैधानिक वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय व्यावसायिक जगत पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। कंपनियां पहले से ही नए श्रम कानूनों और अनुपालन संबंधी खर्चों का दबाव झेल रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने फिलहाल इस प्रस्ताव को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है।उद्योग प्रतिनिधियों का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता और वेतन संहिता के लागू होने से व्यवसायों की देनदारियों में पहले ही 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हो चुकी है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वेतन सीमा में बदलाव भविष्य में किया जाएगा, लेकिन यह कदम सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श और आम सहमति बनाने के बाद ही उठाया जाएगा।

कैबिनेट ने उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को मंजूरी दी

एजेंसी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में उर्वरक विभाग के आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस नीति का उद्देश्य देश में गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए नए निवेश को प्रोत्साहित करना है। इससे घरेलू यूरिया उत्पादन बढ़ेगा और देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय निवेश नीति-2012 (एनआईपी-2012) की तुलना में नई नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें अधिक पारदर्शिता के लिए स्थिर और परिवर्ती लागतों को अलग-अलग करना, आरओई (रिटर्न ऑन इक्विटी) की व्यवहार्य सीमा तय करना, जिसमें

न्यूनतम 12 प्रतिशत और अधिकतम 16 प्रतिशत का प्रावधान है, तथा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करने के लिए चार वर्ष बाद प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर स्थिर लागत को रुपए में परिवर्तित करने की व्यवस्था शामिल है।

सरकारी बयान के मुताबिक, इन प्रावधानों से एनआईपीयू-2026 के तहत स्थापित होने वाले प्रत्येक नए प्लांट पर एनआईपी-2012 की तुलना में 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। नई यूरिया विनिर्माण इकाइयों की स्थापना एनआईपीयू-2026 के दायरे में की जाएगी। इससे पहले यूरिया क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए उर्वरक विभाग ने वर्ष 2012 में नई निवेश नीति (एनआईपी-2012) तैयार की थी। इसका उद्देश्य मौजूदा संयंत्रों के आधुनिकीकरण, विस्तार, बंद पड़ी (ब्राउनफील्ड) इकाइयों को दोबारा शुरू करना और नई परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देना था। एनआईपी-2012 के तहत कुल छह नई यूरिया इकाइयों की स्थापना की गई। इनमें से चार इकाइयां नामित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) के संयुक्त उद्यम (जेवीसी) के माध्यम से और दो इकाइयां निजी कंपनियों द्वारा स्थापित की गईं। हालांकि, इस नीति के तहत नए निवेश की अवधि अक्टूबर 2019 में समाप्त हो गई थी। वर्तमान में देश में 33 यूरिया विनिर्माण इकाइयां संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 269.42 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) है।

नवी मुंबई एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय सेवा की शुरूआत,अबूधाबी के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली उड़ान

एजेंसी
नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय सेवा की शुरुआत हुई, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एयरपोर्ट से अबूधाबी के लिए पहली उड़ान भरी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हवाई अड्डे से अबूधाबी के लिए पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित की। करीब 100 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान भारतीय समयानुसार देर रात 2:55 बजे (आईएसटी) रवाना हुई। इसने करीब 2.30 (ढाई घंटे) का सफर तय कर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबूधाबी हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। एयरलाइन के मुताबिक यह उड़ान एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737 मैक्स 8 विमान से संचालित की गई। उड़ान भरने से पहले विमान के पायलट ने इसे एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण यात्रा बताया। इस उड़ान के साथ जल्दी खराब होने वाले (पेरिशेबल) उत्पादों की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप भी भेजी गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस हफ्ते में 3 बार अबूधाबी के लिए उड़ानें संचालित करेगी। उल्लेखनीय है कि 25 दिसंबर, 2025 को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से घरेलू सेवाएं शुरू हुई थीं। इस एयरपोर्ट का विकास कई चरणों में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनएमआईएएल) कर रही है। यह एक विशेष इकाई है, जिसमें एएएचएल की 74 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि शेष हिस्सेदारी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सिडको) के पास है।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना पर राज्य स्तरीय जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन

एजेंसी
जयपुर। बैंक ऑफ बड़ौदा के संयोजन में कार्यरत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) राजस्थान ने भारत सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस 5.0) पर राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, एसएलबीसी राजस्थान की संयोजक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा की महाप्रबंधक परिमिता मिश्रा, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (आरआईटीआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्येन्द्र कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक राव क्षितिजराज सिंह, एमएसएमई-डीएफओ के निदेशक प्रदीप ओझा, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष महेन्द्र मिश्रा तथा एनसीजीटीसी की सहायक महाप्रबंधक मेधा गुरव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि ईसीएलजीएस 5.0 भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की सकारात्मक नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। यह योजना विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि ईसीएलजीएस 5.0 का उद्देश्य वैश्विक व्यवधानों, विशेषकर पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न तरलता संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे उद्यमों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इससे उद्योगों का संचालन सुचारु रहेगा, रोजगार सुरक्षित होंगे तथा आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। उन्होंने बैंकों से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा उद्यमियों से इसका अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। एसएलबीसी राजस्थान की संयोजक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा की महाप्रबंधक परिमिता मिश्रा ने कहा कि ईसीएलजीएस 5.0 केवल वित्तीय सहायता योजना नहीं, बल्कि आर्थिक पुनरुत्थान का मिशन है। उन्होंने कहा कि बैंकों का दायित्व है कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र उद्यमी तक पहुंचाया जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक राव क्षितिजराज सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों, विभिन्न ऋणदाता संस्थानों, उद्यमियों और लाभार्थियों के साथ एसएलबीसी राजस्थान के प्रमुख एवं उप महाप्रबंधक राज कुमार मीणा भी उपस्थित रहे।

मजबूती के साथ बंद हुआ घरेलू शेयर बाजार, निवेशकों ने कमाये 3.37 लाख करोड़ रुपये

एजेंसी
नई दिल्ली। एक दिन की कमजोरी के बाद घरेलू शेयर बाजार आज वापस हरे निशान में पहुंच कर बंद हुआ। आज के कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी। दिन के पहले सत्र में बाजार मामूली उतार-चढ़ाव का सामना करते हुए लगातार बढ़त के साथ कारोबार करता रहा। हालांकि दोपहर एक बजे के करीब बिकवाली का जोरदार दबाव बन जाने की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक गिरकर कुछ देर के लिए लाल निशान में भी पहुंचे। इसके बाद खरीदारों ने मोर्चा संभाल लिया, जिसकी वजह से इन दोनों सूचकांकों ने वापस हरे निशान में जगह बना ली। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.17 प्रतिशत और निफ्टी 0.11 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। आज बाजार की मजबूती की वजह से निवेशकों को लगभग 3.37 लाख करोड़ रुपये का फायदा हो गया।

बीएसई का सेंसेक्स आज 137.82 अंक की मजबूती के साथ 77,192.76 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होने के थोड़ी देर बाद ही खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया, जिससे इस सूचकांक की चाल में तेजी आ गई। लगातार हो रही खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स 591.33 अंक की मजबूती के साथ 77,646.27 अंक के स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद काफी देर तक यह सूचकांक मामूली उतार-चढ़ाव के साथ दिन के ऊपरी स्तर के करीब ही कारोबार करता रहा। दोपहर एक बजे के थोड़ी देर पहले अचानक बिकवाली का दबाव बनने की वजह से यह सूचकांक ऊपरी स्तर से 663.45 अंक टूट कर 72.12 अंक की कमजोरी के साथ 76,982.82 अंक के स्तर तक गिर गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही खरीदारों ने लिवाली का जोर बना कर इस सूचकांक को दोबारा हरे निशान में पहुंचा दिया। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 202.61 अंक की रिकवरी कर 130.49 अंक की बढ़त के साथ 77,185.43 अंक के स्तर पर बंद हुआ।सेंसेक्स की तरह एनएसई के निफ्टी ने आज 33.80 अंक की छलांग लगा कर 24,085.85 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलने के थोड़ी देर बाद ही खरीदारों ने चौतरफा लिवाली शुरू कर दी, जिससे थोड़ी देर में ही निफ्टी 168.30 अंक की उछाल के साथ 24,220.35 अंक के स्तर तक पहुंच गया। इसके बाद दिन के पहले सत्र में लगातार मामूली उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार होता रहा।

पीयूष गोयल और मारोस शेफकोविच ने की भारत-ईयू एफटीए की प्रगति की समीक्षा, व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ (ईयू) के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस शेफकोविच से मुलाकात कर भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (इंडिया-ईयू एफटीए) के क्रियान्वयन की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों (क्रिटिकल टेक्नोलॉजी) और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं (रेजिलिएंट सप्लाई चेन) में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर भी चर्चा की। इस वर्ष मार्च में भी गोयल और शेफकोविच की मुलाकात कैमरून में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी14) के दौरान हुई थी। उस बैठक में भी दोनों पक्षों ने भारत-ईयू एफटीए को अंतिम रूप देने की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की थी।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया को जनवरी 2026 में नई दिल्ली में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा किए गए ऐलान के बाद आगे बढ़ाया जा रहा है।

ब्रसेल्स में अपने दौरे के दौरान पीयूष गोयल ने यूरोपीय संसद की अंतरराष्ट्रीय व्यापार समिति (आईएनटीए) के अध्यक्ष बर्न्ड लैंगे से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत-ईयू एफटीए से दोनों पक्षों के कारोबार, उद्योगों और लोगों को मिलने वाले व्यापक अवसरों पर चर्चा की, जो भविष्य में समृद्ध आर्थिक साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। गोयल ने बर्न्ड लैंगे को भारत आने का निमंत्रण भी दिया, ताकि दोनों पक्षों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जा सके।

इससे पहले भारत और बेल्जियम ने भी व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स और कार्यबल गतिशीलता (वर्कफोर्स मोबिलिटी) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की थी। पीयूष गोयल ने बेल्जियम के उपप्रधानमंत्री एवं रोजगार, अर्थव्यवस्था और कृषि मंत्री डेविड क्लैरिनवाल के साथ बैठक कर दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श किया।

गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत-ईयू एफटीए की परिवर्तनकारी संभावनाओं पर भी विचार साझा किया और कारोबार तथा दोनों देशों के लोगों के पारस्परिक हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने यूरोपीय संघ के जलवायु, नेट-जीरो और स्वच्छ विकास आयुक्त वॉप्के हूकस्ट्रा से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच स्वच्छ विकास, जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और मजबूत वैल्यू चेन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि दोनों पक्ष अपने साझा नेट-जीरो लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में मिलकर आगे बढ़ सकें।

स्टॉक मार्केट में कुसुमगर लिमिटेड की जोरदार शुरुआत, फायदे में आईपीओ निवेशक

एजेंसी
नई दिल्ली। इंजीनियरिंग फैब्रिक्स और एयरोस्पेस एवं डिफेंस सॉल्यूशंस का निर्माण करने वाली कंपनी कुसुमगर लिमिटेड के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मजबूती के साथ एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 419 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 36.99 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 574 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर इसकी लिस्टिंग 35.80 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 569 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली के सपोर्ट से ये शेयर बीएसई पर 631.35 रुपये और एनएसई पर 625.90 रुपये के अपर सर्किट लेवल तक पहुंच गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही बिकवाली शुरू हो जाने के कारण अपर सर्किट ब्रेक हो गया। बिकवाली का दबाव बनने पर ये शेयर गिरकर 567.95 रुपये के स्तर तक भी आया, लेकिन बाद में खरीदारों ने लिवाली शुरू कर इस शेयर के भाव को दोबारा तेज कर दिया। पूरे दिन के कारोबार के बाद ये शेयर बीएसई पर 604.45 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर 602.80 रुपये के स्तर पर बंद हुए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को लगभग 44 प्रतिशत का फायदा हो गया इस कंपनी का 650 करोड़ रुपये का आईपीओ 08 से 10 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 135.80 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 299.51 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

कैबिनेट ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 62,500 करोड़ रुपए को दी मंजूरी

एजेंसी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (एमपीएमएस) को 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी। इसके जरिए केंद्र की कोशिश मोबाइल के घरेलू उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ाना और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करना है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक यानी पांच साल तक चलेगी। इसका मकसद आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना और डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) में निवेश के जरिए भारतीय मोबाइल फोन ब्रांड के विकास को बढ़ावा देना है। एमपीएमएस के तहत, मैन्युफैक्चरर्स को भारत में बने मोबाइल फोन की योग्य बिक्री पर 2.25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक की अलग-अलग दरों पर इंसेंटिव सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा, यह स्कीम मुख्य पार्ट्स और सब-असेंबली की घरेलू सोर्सिंग से जुड़े 1.5 प्रतिशत तक का अतिरिक्त इंसेंटिव भी देती है। घरेलू ब्रांड्स को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट डिजाइन और आरएंडडी के लिए योग्य बिक्री पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त इंसेंटिव पाने के हकदार होंगे। कैबिनेट के अनुसार, इस स्कीम की अवधि के दौरान लगभग 39 लाख करोड़ रुपए का कुल मोबाइल फोन प्रोडक्शन होने की उम्मीद है, साथ ही देश से हैंडसेट के निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी होगी।एमपीएमएस से लगभग 60,000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने का भी अनुमान है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। कैबिनेट ने कहा कि यह पहल सरकार के 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम की सफलता पर आधारित है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2014-15 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सात गुना और निर्यात में 11 गुना बढ़ोतरी हुई है। भारत अब वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है और देश में इस्तेमाल होने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन घरेलू स्तर पर ही बनाए जाते हैं। सरकार ने कहा कि 2025 में स्मार्टफोन भारत की सबसे बड़ी निर्यात कैटेगरी बनकर उभरी है, जिन्होंने डीजल फ्यूल और कटे हुए हीरे जैसे पारंपरिक निर्यात कैटेगरी को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा, यह नई स्कीम 'बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम' की जगह लेगी, जिसका कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो गया था। सरकार ने कहा कि पीएलआई स्कीम ने भारत को मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के लिए एक ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई।

यात्री वाहनों की थोक बिक्री जून में 24.1 प्रतिशत बढ़कर 3.88 लाख यूनिट्स के पार

एजेंसी
नई दिल्ली। भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री (कंपनियों द्वारा डीलर्स को बिक्री) जून में सालाना आधार पर 24.1 प्रतिशत बढ़कर 3,88,144 यूनिट्स रही है। इससे पिछले वर्ष समान अवधि में यह आंकड़ा 3,12,851 यूनिट्स था। यह जानकारी इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) की ओर से जारी डेटा में दी गई। सियाम के डेटा के मुताबिक, यात्री वाहनों में यूटिलिटी व्हीकल (यूवी) सेगमेंट लगातार बढ़ रहा है और जून में इसकी सालाना वृद्धि दर 19.9 प्रतिशत रही और वॉल्यूम 2,17,228 यूनिट्स रही। यात्री गाड़ियों की बिक्री सालाना आधार पर 15.7 प्रतिशत बढ़कर 98,610 यूनिट्स हो गई है। वैन की बिक्री सालाना आधार पर 9.5 प्रतिशत बढ़कर 10,230 यूनिट्स पर पहुंच गई है। दोपहिया वाहन श्रेणी ने भी मजबूत रफ्तार बनाए रखी। जून में कंपनियों की ओर से डीलरों को भेजे गए दोपहिया वाहनों की संख्या 18.6 प्रतिशत बढ़कर 18,51,400 यूनिट्स हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह आंकड़ा 15,61,283 यूनिट्स पर था। दोपहिया वाहनों में स्कूटर सबसे तेजी से बढ़ने वाली श्रेणी रही। इसकी घरेलू बिक्री 39.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 7,44,823 यूनिट्स पर पहुंच गई। वहीं, मोटरसाइकिल की बिक्री 6.4 प्रतिशत बढ़कर 10,56,422 यूनिट्स हो गई, जबकि मोपेड की बिक्री कम आधार के चलते 50.4 प्रतिशत बढ़कर 50,155 यूनिट्स हो गई है। तिपहिया वाहनों की डीलरों को बिक्री सालाना आधार पर 26.1 प्रतिशत बढ़कर 77,951 यूनिट्स हो गई है, जबकि पिछले वर्ष जून में यह आंकड़ा 61,828 यूनिट्स पर था। जून में पैसेंजर कैरियर वाहनों की बिक्री 25 प्रतिशत बढ़कर 64,181 यूनिट्स रही, जबकि गुड्स कैरियर वाहनों की बिक्री 29.4 प्रतिशत बढ़कर 11,828 यूनिट्स पर पहुंच गई। इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों ने भी मजबूत वृद्धि दर्ज की। ई-रिक्शा की बिक्री 52.4 प्रतिशत बढ़कर 1,590 यूनिट्स हो गई। सियाम के आंकड़ों के अनुसार, जून में वाहन निर्यात भी मजबूत बना रहा। कुल वाहन निर्यात सालाना आधार पर 34 प्रतिशत बढ़कर 6,73,105 यूनिट्स पर पहुंच गया है।

आरबीआई ने बैंक बोर्ड के संचालन मानदंडों में संशोधन किया, नए नियम एक अक्टूबर से होंगे प्रभावी

एजेंसी
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीअई) ने बैंक निदेशक मंडल के सामने रखे जाने वाले मामलों में अंतिम संशोधनों की घोषणा की है। आरबीआई के नये नियम इस साल एक अक्टूबर से लागू होंगे। इसका मकसद बैंकों में कामकाज को आसान बनाना है। आरबीआई ने जारी एक अधिसूचना में बताया कि नए नियम इस साल एक अक्टूबर से लागू होंगे। आरबीआई ने कहा कि नियमों का नया सेट सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मकसद बैंक निदेशक मंडल (बोर्ड) को यह स्वतंत्रता देना है कि वे हर बैंक की खास प्राथमिकताओं के आधार पर अपना एजेंडा तय कर सकें। हालांकि, आरबीआई ने यह भी साफ किया कि जोखिम, नियमों का पालन, वित्तीय प्रदर्शन और ग्राहकों की सुरक्षा जैसे अहम मामलों पर बोर्ड की निगरानी बनी रहेगी। केंद्रीय बैंक के बदले हुए नए नियमों के मुताबिक बैंक बोर्ड बैठकों में लिए गए फैसलों को लागू करने का तरीका खुद तय कर सकता है। केंद्रीय बैंक ने कार्रवाई रिपोर्ट व्यवस्था को जारी रखने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया। केंद्रीय बैंक ने संबंधित पक्षों की राय के आधार पर महत्वपूर्ण मामलों को परिभाषित करने की जरूरत को खत्म कर दिया है।

भारत-यूके व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए निर्यात और प्रौद्योगिकी के नए अवसर खुलेंगे- उद्योग संगठन

एजेंसी
नई दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता बुधवार से लागू हो गया। उद्योग जगत के प्रमुख संगठनों का कहना है कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर खोलेगा, प्रौद्योगिकी साझेदारी को मजबूत करेगा और वैश्विक बाजार में भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। समझौते के लागू होने के अवसर पर पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने 'इंडिया-यूके सीईटीए: निर्यात अवसरों और बाजार पहुंच के लिए एक रणनीतिक मार्गदर्शिका' शीर्षक से एक शोध रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में द्विपक्षीय व्यापार, विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, तकनीकी सहयोग, बाजार पहुंच और समझौते से अधिकतम लाभ उठाने के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत का ब्रिटेन को होने वाला निर्यात अब तेजी से उच्च मूल्य वाले विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) उत्पादों की ओर बढ़ रहा है, जिसमें उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, औद्योगिक नीतियों और विनिर्माण

क्षेत्र की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मार्टफोन, दवाइयां (फार्मास्यूटिकल्स), एल्युमिनियम ऑक्साइड, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, मशीनरी के पुर्जे, फुटवियर और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद भारत के सबसे तेजी से बढ़ते निर्यात क्षेत्रों में शामिल हो गए हैं। पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष राजीव जुनेजा ने कहा कि भारत-यूके सीईटीए में द्विपक्षीय व्यापार को पारंपरिक वस्तु-आधारित संबंधों से आगे बढ़ाकर प्रौद्योगिकी आधारित रणनीतिक आर्थिक साझेदारी में बदलने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमता और ब्रिटेन की नवाचार एवं उन्नत तकनीक में विशेषज्ञता मिलकर निर्यात बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (ग्लोबल वैल्यू चेन) में भारत की भागीदारी को मजबूत करने के बड़े अवसर पैदा करती हैं। पीएचडीसीसीआई के महासचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. रंजीत मेहता ने कहा कि यह समझौता भारतीय उद्योगों को अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, विशेष सामग्री (स्पेशियलिटी मैटेरियल्स) और डिजिटल सेवाओं जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसी तरह भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने भी इस समझौते के लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इससे भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे तथा भारतीय उद्योगों के लिए नए व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे।

बनर्जी ने कहा कि यह समझौता इस बात का भी प्रमाण है कि भारत अब ऐसे संतुलित और उच्च गुणवत्ता वाले व्यापार समझौतों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और मजबूत बनाते हैं।

ईरान का ऐलान- फिलहाल बातचीत की कोई योजना नहीं, अमेरिकी हमलों का देंगे कड़ा जवाब

एजेंसी

तेहरान। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल उसकी अमेरिका के साथ किसी भी तरह की वार्ता की कोई योजना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बुधवार को कहा कि देश की प्राथमिकता अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है और अमेरिकी हमलों का दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। तेहरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के दामाद की श्रद्धांजलि सभा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बघाई ने कहा, फिलहाल हमारी किसी वार्ता की योजना नहीं है। हमारा पूरा ध्यान देश की रक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका किसी समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन करता है, तो ईरान भी ऐसे किसी समझौते का पालन नहीं करेगा। बघाई ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने संघर्ष विराम लागू होने के शुरुआती चरण से ही उसका सम्मान नहीं किया और अपने दायित्वों की अनदेखी की है। इसी बीच ईरान की अर्द्ध-सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने दावा किया कि अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित हेंगाम द्वीप पर हवाई हमला किया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और अमेरिकी प्रशासन की ओर से भी इस संबंध में तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

ईरान पर अमेरिकी हमले में 30 की मौत, ट्रम्प ने अगले 3 दिन और बड़े हमले की चेतावनी दी

तेहरान/वॉशिंगटन। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि हाल के अमेरिकी हवाई हमलों में 260 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन करमनपौर के अनुसार, घायलों में कम से कम तीन महिलाएं और छह बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 222 घायलों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। करमनपौर ने कहा कि ये सभी लोग ईरान पर हाल में हुए अमेरिकी हमलों की ताजा लहर में घायल हुए हैं। हालांकि, उन्होंने हमलों की सटीक समयावधि का उल्लेख नहीं किया। इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। इससे पहले ईरान सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी ने बताया था कि हाल के दिनों में दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमलों में 30 से अधिक नागरिकों की मौत हुई है। ईरानी सेना ने दावा किया कि देश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित एक सैन्य अड्डे पर रातभर हुए अमेरिकी हमलों में सात सैन्यकर्मी भी मारे गए। दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को और तेज करने की रणनीति पर चर्चा की गई।

ब्रिटेन में 40 साल पुराने राममंदिर की जमीन पर विवाद, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

लंदन। ब्रिटेन के पीटरबरो शहर मस्थित करीब 40 साल पुराने राममंदिर की जमीन को लेकर विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। पीटरबरो सिटी काउंसिल द्वारा मंदिर परिसर को यूके इस्लामिक मिशन (यूकेआईएम) को बेचने के फैसले के खिलाफ हिंदू संगठन, भारत हिंदू समाज (बीएचएस) ने न्यायिक समीक्षा की मांग की है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीटरबरो सिटी काउंसिल की ओर से पेश अधिवक्ता कैथरीन रोलैंड्स ने दलील दी कि मंदिर परिसर को यूके इस्लामिक मिशन को बेचने का फैसला कानून के दायरे में है और इसे गैरकानूनी नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी समुदाय की धार्मिक पहचान को निर्णय प्रक्रिया में ध्यान में रखा जाता है लेकिन वही अकेले किसी फैसले का आधार नहीं बन सकती। काउंसिल ने अदालत को बताया कि फिलहाल भारत हिंदू समाज को परिसर में किरायेदारी का अधिकार प्राप्त है और पुनर्विकास शुरू होने तक वह वहां रह सकता है। इसके बाद उन्हें परिसर खाली करना होगा। काउंसिल का कहना है कि वह हिंदू समुदाय के महत्व को स्वीकार करती है और चाहती है कि समुदाय पीटरबरो में बना रहे।

डरबन में हजारों श्रद्धालुओं ने 27 बार किया हनुमान चालीसा पाठ, मोदी ने दी शुभकामनाएं

डरबन। आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संगठन चिन्मय मिशन ने अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दक्षिण अफ्रीका के डरबन स्थित चैट्सवर्थ स्टेडियम में मैन टू हनुमान कार्यक्रम के तहत विशाल हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया, जिसमें 17,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने 27 बार सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। इससे कुल 4.5 लाख से अधिक सामूहिक पाठ पूरे हुए। पाठ के बाद भगवान हनुमान के लिए आटे, घी, चीनी से बनी पारंपरिक मिठाई 'रोट' को हर भक्त को प्रसाद के रूप में बांटा गया। यह कार्यक्रम चिन्मय मिशन साउथ अफ्रीका द्वारा चिन्मय आंदोलन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक 'चिन्मय अमृत महोत्सव' के हिस्से के तौर पर किया गया था। स्टेडियम केसरिया रंग, भक्ति और एकता के सागर में बदल गया। यह कार्यक्रम सिर्फ़ एक धार्मिक सभा नहीं, बल्कि भक्ति, एकता, सेवा और सांस्कृतिक गौरव का एक शानदार उत्सव बन गया। जब 17,000 से ज़्यादा भक्त केसरिया झंडों के बीच एक साथ खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तब चिन्मय मिशन ने अफ्रीका के इतिहास और सनातन धर्म पर वैश्विक चर्चा में एक यादगार पल रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि दक्षिण अफ्रीका में चिन्मय मिशन के अमृत महोत्सव के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। यह ऐतिहासिक उत्सव हमारे चिन्मय मिशन की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए साढ़े सात दशकों की समर्पित सेवा को दर्शाता है।

ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर ने संसद को किया 'गुडबाय', बोले- ये मेरे राजनीतिक सफर का अंत

एजेंसी

लंदन। कीर स्टार्मर ने बतौर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आखिरी बार हाउस ऑफ कॉमंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह देश को उस स्थिति से बेहतर हालात में छोड़कर जा रहे हैं, जैसी स्थिति में उन्होंने कार्यभार संभाला था। संसद में प्रश्नकाल के दौरान लेबर पार्टी की सांसद और स्टार्मर की करीबी सहयोगी कैरोलिन हैरिस ने कहा, 'जब स्टार्मर ने पार्टी का नेतृत्व संभाला था, तब बहुत कम लोगों को विश्वास था कि वह जरूरी बदलाव ला पाएंगे। आज उनके नेतृत्व की बदौलत बच्चे अधिक न्यायपूर्ण ब्रिटेन में बड़े हो रहे हैं और देश वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है।' हैरिस ने कहा कि पूरे कार्यकाल के दौरान स्टार्मर की शालीनता और साहस लगातार दिखाई दिया। उनकी बातों के जवाब में स्टार्मर ने उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'डिस्पैच बॉक्स से यह

मेरा आखिरी जवाब होगा।'

उन्होंने कहा, 'हर प्रधानमंत्री जानता है कि जब वह यह जिम्मेदारी संभालता है, तो एक दिन उसे इसे किसी और को सौंपना होगा। वह दिन अब मेरे लिए आ गया है।' स्टार्मर ने कहा कि यह उनके राजनीतिक सफर का अंत है। उन्होंने कहा, 'छह वर्षों में हमने 2019 की ऐतिहासिक हार से 2024 की ऐतिहासिक जीत तक का सफर तय किया और सरकार में दो वर्षों के बाद मैं देश को पहले से बेहतर स्थिति में छोड़कर जा रहा हूं। मुझे हमारी सभी उपलब्धियों पर गर्व है।' उन्होंने संसद अध्यक्ष, संसद के कर्मचारियों और अपने निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत लोगों का उनके सहयोग और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने सिविल सेवा के अधिकारियों, अपनी राजनीतिक टीम और पार्टी के सहयोगियों का भी आभार जताया। स्टार्मर ने कहा कि उनकी टीम ने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया और उनके लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार रही। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें उन सभी पर गर्व है। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को पूर्ण समर्थन देने का भरोसा भी दिलाया और संसद के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना की। अपने संबोधन के अंत में स्टार्मर ने कहा कि जिन लोगों का जीवन उनकी सरकार के दौरान बेहतर हुआ और जो समाज में अक्सर अनसुने रह जाते हैं, वही उनके राजनीति में आने की सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं तुम सबसे प्यार करता हूं। गुडबाय।' ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 22 जून 2026 को डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफे की घोषणा की थी।

यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री होंगे सर्गी कोरेट्स्की, जेलेंस्की ने किया समर्थन

एजेंसी

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सरकारी ऊर्जा कंपनी नाफ्टोगाज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्गी कोरेट्स्की को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन किया है।

यह फैसला प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको के इस सप्ताह इस्तीफा देने के बाद सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा, हमारी प्राथमिकता स्पष्ट है- आगामी सर्दियों की तैयारी। सभी आवश्यक विचार-विमर्श के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री पद के लिए सर्गी कोरेट्स्की सबसे उपयुक्त और तैयार उम्मीदवार हैं। इससे पहले, स्विरिडेंको ने प्रधानमंत्री पद संभालने के लगभग एक वर्ष बाद इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सरकार में इस फेरबदल की घोषणा तो की, लेकिन इसके पीछे कोई विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि देश नई चुनौतियों और प्राथमिकताओं के अनुरूप अपनी राजनीतिक रणनीति में बदलाव कर रहा है। यूक्रेन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद करती है। हालांकि संसद में राष्ट्रपति जेलेंस्की की पार्टी के पास बहुमत होने के कारण माना जा रहा है कि सर्गी कोरेट्स्की के नाम पर आसानी से मुहर लग जाएगी। कोरेट्स्की वर्तमान में नाफ्टोगाज के प्रमुख हैं और ऊर्जा क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें ऐसे समय जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जब रूस के लगातार हमलों के कारण यूक्रेन का ऊर्जा ढांचा गंभीर दबाव में है। आगामी सर्दियों से पहले ऊर्जा आपूर्ति को सुचारु बनाए रखना नई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल होगा।

ब्रेक्जिट के बाद स्पेन-जिब्राल्टर सीमा पर बड़ी राहत, नियमित जांच खत्म

एजेंसी

जिब्राल्टर। यूरोपीय संघ (ईयू) और ब्रिटेन के बीच पोस्ट-ब्रेक्जिट एग्रीमेंट (ब्रेक्जिट के बाद हुए नए समझौते) के तहत बुधवार से स्पेन और जिब्राल्टर के बीच भूमि सीमा पर नियमित जांच (रूटीन बॉर्डर चेक) समाप्त कर दी गई। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच लोगों और सामान की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगी। ब्रसेल्स में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए और बुधवार से अंतरिम रूप से इसे लागू कर दिया गया। हालांकि, इसे यूरोपीय संसद की मंजूरी और दोनों पक्षों की औपचारिक अनुमोदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम रूप मिलेगा। समझौता लागू होने से पहले जिब्राल्टर और पड़ोसी स्पेनिश शहर ला लीनेआ दे ला कॉन्सेप्सियोन के सैकड़ों निवासी सीमा के पास एकत्र हुए। बुधवार आधी रात के बाद यूरोपीय संघ का आधिकारिक गान 'ओड टू जॉय' बजाया गया और सीमा पर चेकप्वाइंट हटा दिया गया। इसके बाद पैदल यात्री, कारें और मोटरसाइकिलें बिना नियमित पासपोर्ट या पहचान जांच के सीमा पार करने लगीं। समझौते के तहत जिब्राल्टर और स्पेन के बीच सामान और श्रमिकों की आवाजाही को काफी आसान बनाया जाएगा, जिससे जिब्राल्टर और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

यूरोपीय आयोग ने कहा कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य पूरे क्षेत्र की समृद्धि सुनिश्चित करना है। आयोग के अनुसार, इससे जिब्राल्टर और स्पेन के अधिकारियों के बीच सहयोग और बेहतर होगा, जबकि शेंगेन क्षेत्र, यूरोपीय संघ के एकल बाजार और सीमा शुल्क संघ की सुरक्षा भी बरकरार रहेगी। ब्रिटिश सरकार ने जारी बयान में कहा कि यह ऐतिहासिक समझौता उन 15,000 से अधिक लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो हर दिन स्पेन और जिब्राल्टर के बीच काम के लिए सीमा पार करते हैं। ब्रेक्जिट के बाद वर्ष 2020 से ही इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच बातचीत चल रही थी।

जून 2025 में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्पेन और जिब्राल्टर के बीच व्यापक सहमति बनने के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया। प्रक्रिया के तहत समझौते को इस वर्ष सर्दियों में यूरोपीय संसद की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वहीं, यूरोपीय संघ की परिषद ने 15 जुलाई 2026 से इसके अंतरिम क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है।

एमवी जीएफएस गैलेक्सी हादसा: दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जताया दुख

एजेंसी

दुबई। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने 12 जुलाई 2026 को वाणिज्यिक जहाज एमवी जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दूतावास ने बयान जारी कर पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है। एक्स पोस्ट पर जारी बयान में कहा, '12 जुलाई 2026 को वाणिज्यिक जहाज एमवी जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

वाणिज्य दूतावास शोक संतप्त परिवार के संपर्क में है और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित यूएई अधिकारियों और शिपिंग कंपनी के साथ करीबी समन्वय कर रहा है।' ओमान तट के पास रविवार को 'जीएफएस ग्लैक्सी' नामक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ था। इसके बाद से ही पुणे के मरीन इंजीनियर हेरंब करमरकर लापता थे। इस संबंध में जानकारी सामने आई थी। मौत की पुष्टि हेरंब करमरकर के परिवार और ससुर विवेक टंडन ने की।

ओमान के तट के पास भारतीय नागरिकों को ले जा रहे कमर्शियल जहाज जीएफएस ग्लैक्सी पर रविवार को हमला हुआ था। हेरंब करमरकर के ससुर विवेक टंडन ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'हमारा 30 साल का बच्चा था, कोई बुजुर्ग नहीं था। हमारी भारत सरकार से यही विनती है कि हमारे बच्चे की बॉडी सही सलामत हमें हैंड ओवर की जाए और उसे उसके घर पहुंचा दिया जाए।' इससे पहले, भारत ने इस हमले की निंदा की और इस इलाके में कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाओं को 'बेहद चिंताजनक' बताया था।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और जारी खोज और बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा रहा है। मंत्रालय ने सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का धन्यवाद भी किया।

इजरायल के पीएम नेतन्याहू जाएंगे अमेरिका, ट्रंप से मुलाकात स्पष्ट नहीं

एजेंसी

तेल अवीव। ईरान के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार अमेरिका जा सकते हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शनिवार को अमेरिका की यात्रा करेंगे। अधिकारी ने कहा कि नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी या नहीं। द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू अमेरिका के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के स्मृति कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ग्राहम इजरायल के प्रमुख समर्थकों में से एक थे, और शनिवार को उनका निधन हो गया था। हालांकि, उनके अंतिम संस्कार की तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।

एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच किसी बैठक का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है।

अगर नेतन्याहू की यह यात्रा तय होती है, तो ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद यह उनकी पहली अमेरिका यात्रा होगी। उनकी पिछली यात्रा फरवरी के मध्य में हुई थी, जो अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू करने से कुछ सप्ताह पहले की बात है।

फरवरी 2026 में वो अमेरिका गए थे। ट्रंप और उनके बीच मुलाकात हुई थी जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह अब भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए उसके साथ समझौते की संभावना तलाश रहे हैं। यह बयान नेतन्याहू के साथ तीन घंटे की बैठक के बाद आया था, जिसमें माना गया था कि इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिका से ईरान के खिलाफ और अधिक सख्त सैन्य कार्रवाई की मांग करेंगे।

ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद नेतन्याहू की व्हाइट हाउस की छठी यात्रा बिना किसी सार्वजनिक बयान के समाप्त हुई थी। इस अचानक आयोजित बैठक के नतीजों की जानकारी ट्रंप ने ऑनलाइन पोस्ट के जरिए दी थी।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'इसके अलावा कुछ भी निश्चित रूप से तय नहीं हुआ कि मैंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि कोई समझौता हो सकता है या नहीं।' उन्होंने आगे कहा, 'अगर ऐसा संभव होता है, तो मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि यह मेरी प्राथमिकता होगी। अगर ऐसा नहीं होता, तो हमें देखना होगा कि इसका परिणाम क्या होता है।'

अमेरिका ने ईरान के हथियार खरीद नेटवर्क पर लगाए नए प्रतिबंध, रूस और नाइजीरिया से जुड़े लोग भी निशाने पर

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिका ने ईरान के कथित हथियार खरीद नेटवर्क को बाधित करने के उद्देश्य से कई व्यक्तियों और संस्थाओं पर नए प्रतिबंध (सैंक्शन) लगाए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय (ट्रेजरी विभाग) ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि ये प्रतिबंध ऐसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को निशाना बनाते हैं, जो ईरान को हथियारों की खरीद और आपूर्ति में मदद कर रहे थे। प्रतिबंधों की सूची में ईरान और रूस के नागरिकों के अलावा ईरान, रूस और नाइजीरिया में स्थित कई संस्थाएं भी शामिल हैं। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि यह नेटवर्क ईरान की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न देशों में फैली कंपनियों और वित्तीय माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा था। ट्रेजरी विभाग के अनुसार, प्रतिबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की भूमिका छिपाने के लिए विदेशी विमानन और परिवहन कंपनियों, वित्तीय चैनलों तथा यात्रा समन्वयकों का उपयोग किया। इन माध्यमों से हथियारों से संबंधित सामग्री और कर्मियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही कराई जाती थी। ये प्रतिबंध ऐसे समय लगाए गए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव के बाद। ट्रम्प प्रशासन ईरान पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की रणनीति के तहत लगातार नए प्रतिबंध लागू कर रहा है। इससे पहले, मई में अमेरिका ने चीन और हांगकांग की कई कंपनियों तथा व्यक्तियों पर ईरान के हथियार कार्यक्रम में सहयोग देने के आरोप में प्रतिबंध लगाए थे। वहीं जून में भी अमेरिका ने 11 व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रतिबंधित किया था।

पीओके में हालात तनावपूर्ण, जेएएसी नेता ने इस्लामाबाद के 'फेक नैरेटिव' पर किया प्रहार

एजेंसी

स्लामाबाद। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में बढ़ता असंतोष लगातार 36वें दिन भी जारी रहा। रावलाकोट में हजारों लोग जुटे, जहां जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के नेता सरदार अम्मान खान ने पाकिस्तान पर क्षेत्र पर 'जबरन कब्जा' करने का आरोप लगाया और इस इलाके को लेकर इस्लामाबाद के लंबे समय से चले आ रहे 'फेक नैरेटिव' (फर्जी दावे) को खारिज किया। सभा को संबोधित करते हुए खान ने पीओके को 'विवादित क्षेत्र' कहे जाने का विरोध करते हुए कहा, 'यह कोई विवादित क्षेत्र नहीं है; यह एक कब्जे वाला क्षेत्र है। इस पर जबरन कब्जा किया गया है।' उन्होंने कहा कि यह आंदोलन 'जीत' हासिल होने तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े।

रावलाकोट में हुई विशाल सभा में पाकिस्तान सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक उन्हें सफलता नहीं मिल जाती।

इस बीच, यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) ने पीओके में जारी प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षाबलों द्वारा सात नागरिकों की कथित हत्या की कड़ी निंदा की। अंग्रेजी दैनिक डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, रावलाकोट में बढ़ते सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों के दौरान गोलीबारी में सात और नागरिकों की मौत हुई। यूकेपीएनपी ने इन मौतों, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित बल प्रयोग, जबरन गायब किए जाने, मनमानी गिरफ्तारियों, डराने-धमकाने और नागरिकों पर लगाए गए प्रतिबंधों की 'स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच' की मांग की। पार्टी ने पाकिस्तान सरकार से शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ अत्यधिक और घातक बल के इस्तेमाल को तुरंत रोकने, कथित अवैध हत्याओं, मनमानी गिरफ्तारियों और जबरन गायब करने की घटनाओं पर रोक लगाने तथा सभी हिरासत में लिए गए लोगों को सक्षम अदालतों के सामने पेश कर उचित कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की अपील की।यूकेपीएनपी ने अधिकारियों से खाद्य सामग्री, दवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और मानवीय सहायता तक निर्बाध पहुंच बहाल करने, संचार प्रतिबंध हटाने और क्षेत्र में लोगों की आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की भी मांग की। पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पीओके में एक स्वतंत्र फैक्ट-चेक मिशन भेजने, कथित मानवाधिकार उल्लंघनों और मौतों की निष्पक्ष जांच कराने तथा जमीनी स्थिति की निगरानी करने की अपील की।

दक्षिण-पूर्व ईरान में अमेरिकी हमले में 7 सैनिकों की मौत; सेना बोली, 'सही समय पर देंगे जवाब'

एजेंसी

तेहरान। ईरानी सेना ने कहा है कि दक्षिण-पूर्व ईरान के बमपूर गैरिसन (सैन्य ठिकाने) पर हुए अमेरिकी हमले का जवाब दिया जाएगा। सेना ने इस हमले को 'कायरना' करार देते हुए कहा कि इसका निर्णायक जवाब उचित समय पर दिया जाएगा। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार, सेना के बयान में कहा गया कि अमेरिका ने ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत के इरानशहर इलाके में स्थित बमपूर बैरक पर 13 मिसाइलें दागीं। इस हमले में 388वीं ब्रिगेड के सात सैन्यकर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। ईरानी सेना ने बताया कि सैन्य अड्डे पर मौजूद 'सुरक्षा उपायों' के कारण हताहतों की संख्या को सीमित किया जा सका। सेना के अनुसार, अमेरिकी हमलों का उद्देश्य अधिकतम नुकसान पहुंचाना था, और इसके लिए सैन्य अड्डे के गेस्टहाउस, सुरक्षा चौकियों और आवासीय फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। सेना ने कहा कि

यह हमला केवल सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को हताहत करना था।इस बीच, ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि पिछले कुछ दिनों में दक्षिणी ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों में 30 से अधिक आम नागरिकों की मौत हुई। वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता होसैन केरमनपौर ने बताया कि ताजा हमलों में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।सोशल मीडिया मंच एक्स पोस्ट में मोहाजेरानी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, 'हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और मारे गए लोगों की स्मृति का सम्मान करते हैं।' उन्होंने कहा कि सरकार पूरी ताकत के साथ जनता के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने दक्षिणी ईरान को देश का 'धड़कता हुआ दिल' बताया। वहीं, बुशहर प्रांत के गवर्नर मोहम्मद मोजफ्फरी ने कहा कि अमेरिका ने पश्चिमी तटीय शहर में तीन स्थानों को निशाना बनाया।

नेपाल में मानसून का व्यापक असर, कई प्रांतों में भारी बारिश का अलर्ट

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल में मानसून का प्रभाव पूरे देश में बना हुआ है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने कई प्रांतों में भारी वर्षा की संभावना जताते हुए सतर्क रहने की अपील की है। विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार मानसूनी निम्न दाब रेखा इस समय नेपाल के तराई क्षेत्र के पास अपनी औसत स्थिति से थोड़ा उत्तर की ओर स्थित है। देशभर में सामान्यतः बादल छाए हुए हैं तथा कोशी, बागमती, गंडकी और लुम्बिनी प्रांत के विभिन्न स्थानों के साथ-साथ कर्णाली प्रांत के कुछ इलाकों में मध्यम वर्षा हो रही है। महाशाखा ने देशभर में सामान्य से पूर्णतः बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पहाड़ी और तराई क्षेत्रों के कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। कोशी, बागमती, गंडकी और लुम्बिनी प्रांत के पहाड़ी जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। मधेश, बागमती, गंडकी और लुम्बिनी प्रांत के तराई क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर भी भारी बारिश की संभावना है। कोशी, बागमती और गंडकी प्रांत के उच्च हिमाली क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा के साथ हिमपात भी हो सकता है। इसी प्रकार लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रांत के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान है। कई पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है।

2050 तक कैंसर मामलों के लगभग दोगुना होने की आशंका – विश्व स्वास्थ्य संगठन

एजेंसी

वाशिंगटन। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी दी है कि अगर देशों ने रोकथाम, शुरुआती पहचान और उपचार को मज़बूत करने के लिए तत्काल क़दम नहीं उठाए, तो 2050 तक दुनिया भर में कैंसर के नए मामलों की संख्या हर साल लगभग 3 करोड़ 50 लाख तक पहुँच सकती है. WHO की एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि अमीर और ग़रीब देशों में कैंसर से बचने की सम्भावनाओं में बड़ा अन्तर है. इसी रिपोर्ट के आधार पर यह चेतावनी दी गई है.हर साल एक करोड़ मौतेंविश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की विशेष एजेंसी, कैंसर पर शोध के लिए अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी (IARC) के साथ तैयार की गई 'कैंसर पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2026' में बताया गया है कि कैंसर के कारण पहले ही हर दिन 26 हज़ार से अधिक लोगों की मौत हो रही है. रिपोर्ट के अनुसार, हर साल कैंसर के अनुमानित 2 करोड़ 6 लाख नए मामले सामने आते हैं और लगभग एक करोड़ लोगों की मौत होती है. इस तरह,हृदय सम्बन्धी बीमारियों के बाद कैंसर दुनिया में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है.रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि तम्बाकू नियंत्रण, टीकाकरण और कैंसर की रोकथाम में प्रगति के बावजूद, लाखों लोग अब भी जीवनरक्षक देखभाल तक पहुँच में गहरी असमानताओं का सामना कर रहे हैं. WHO महानिदेशक डॉक्टर टैड्रॉस एडहेनॉम घेब्रेयेसस ने कहा, 'कैंसर एक बेहद निजी बीमारी है, जो लगभग हम सभी के जीवन को किसी न किसी रूप में छूती है. लेकिन कोई व्यक्ति कैंसर से बच पाएगा या नहीं, यह कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि उसका जन्म कहाँ हुआ या उसकी आमदनी कितनी है.' उन्होंने कहा कि 'इस रिपोर्ट में दर्ज असमानताएँ अपरिहार्य नहीं हैं. ये नीतिगत विकल्पों का परिणाम हैं और मज़बूत व एकजुट कार्रवाई के ज़रिये इन्हें बदला जा सकता है. 'गहरी असमानताएँरिपोर्ट के अनुसार, अमीर और ग़रीब देशों में कैंसर से जीवित रहने की दरों में बड़ा अन्तर है. उच्च आय वाले देशों में स्तन कैंसर से पीड़ित 87 प्रतिशत महिलाएँ निदान के बाद कम से कम पाँच वर्ष तक जीवित रहती हैं, जबकि निम्न आय वाले देशों में यह आँकड़ा घटकर लगभग 42 प्रतिशत रह जाता है.वर्तमान में तीन में से एक से भी कम देश अपने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पैकेजों में कैंसर देखभाल को शामिल करते हैं. इसके कारण अनेक मरीज़ आवश्यक निदान, उपचार या सहायक देखभाल तक पहुँच से वंचित रह जाते हैं.WHO ने इस बीमारी के भारी सामाजिक और आर्थिक बोझ को भी रेखांकित किया है. कैंसर से प्रभावित लोगों पर किए गए अपने पहले वैश्विक सर्वेक्षण में WHO ने पाया कि -कम से कम 45 प्रतिशत लोग वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हैं.आधे से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों की बात करते हैं. लगभग सभी देखभालकर्ताओं पर भारी दबाव पड़ता है, जिनमें बिना वेतन देखभाल की ज़िम्मेदारियाँ और सामाजिक अलगाव शामिल हैं.महाद्वीपों के बीच अन्तर2024 में दुनिया भर में कैंसर के कुल मामलों और मौतों में आधे से अधिक एशिया में दर्ज किए गए. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा एशिया में रहता है.योरोप में दुनिया की केवल लगभग नौ प्रतिशत आबादी रहती है, लेकिन वहाँ कैंसर के 21 प्रतिशत मामले और 20 प्रतिशत मौतें दर्ज की गईं. इससे पता चलता है कि वहाँ आबादी के अनुपात में कैंसर का बोझ काफ़ी अधिक है.वहीं, अफ़्रीका के कई देशों और एशिया के कुछ हिस्सों में कैंसर के मामले अपेक्षाकृत कम हैं, लेकिन उनसे होने वाली मौतों की दर काफ़ी अधिक है.फेफड़ों का कैंसर सबसे घातकदुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण अब भी फेफड़ों का कैंसर है।

page 1 and 8 July 17_page 1 Mar 25 final ds.qxd 7/17/2026 1:08 AM Page 2

एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद से यूपी के किसानों को मिल रहा बड़ा लाभ, अनाज की खरीद में बना कीर्तिमान

नौ साल में योगी सरकार ने धान खरीद से 80.39 लाख किसानों को पहुंचाया लाभ, 1.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे खातों में पहुंचे

कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास
पारदर्शी व्यवस्था ने बढ़ाया किसानों का विश्वास
धान, बाजरा, ज्वार और मक्का की रिकॉर्ड खरीद, किसान हितैषी नीतियों से यूपी में खेती बनी अधिक लाभकारी

लखनऊ, 16 जुलाई। उत्तर प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में योगी सरकार की सरकारी खरीद नीति ने पिछले नौ वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पारदर्शी खरीद व्यवस्था, समयबद्ध भुगतान और डिजिटल प्रक्रिया के कारण प्रदेश के किसानों का सरकारी खरीद प्रणाली पर भरोसा मजबूत हुआ है। धान खरीद के क्षेत्र में राज्य ने नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक 80,39,539 किसानों से धान की खरीद की और उनके बैंक खातों में 1.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है।

योगी सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया है। प्रदेशभर में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई, किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई, डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था लागू की गई और भुगतान सीधे बैंक खातों में भेजने की प्रणाली को मजबूत किया गया। इससे किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ समय पर मिल रहा है।

योगी सरकार ने धान और गेहूं तक ही खरीद व्यवस्था को सीमित नहीं रखा, बल्कि पोषक अनाजों को भी प्राथमिकता दी। वर्ष 2022-23 से पहली बार बाजरा की सरकारी खरीद शुरू की गई। वर्ष 2025-26 तक 1,48,718 किसानों से 7,13,759.88 मीट्रिक टन बाजरा खरीदकर 1,854 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 से पहली बार ज्वार की सरकारी खरीद प्रारंभ हुई, जिसके तहत पिछले तीन वर्षों में 26,972 किसानों को 363.35 करोड़ रुपए का भुगतान मिला। वहीं वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक मक्का खरीद के माध्यम से 34,578 किसानों को 582.04 रुपए करोड़ का भुगतान किया गया। इससे मोटे अनाजों की खेती करने वाले किसानों को भी एमएसपी का लाभ मिला और उनकी आय में वृद्धि हुई।

खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खरीद व्यवस्था केवल फसल खरीद का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन चुकी है। समय पर भुगतान, पारदर्शी खरीद प्रक्रिया और खरीद केंद्रों की बेहतर उपलब्धता ने किसानों का भरोसा बढ़ाया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है और कृषि क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बना है। योगी सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण खेती को अधिक लाभकारी बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक का अग्रणी केंद्र बनेगा उत्तर प्रदेश : मुख्यमंत्री

***लखनऊ, 16 जुलाई।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि नोएडा में विकसित होने वाली प्रगति परियोजना प्रदेश को विश्वस्तरीय रोबोटिक्स एवं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग का आधार प्रदान करेगी, जबकि लखनऊ और नोएडा में स्थापित किए जा रहे यू हब अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप, उद्योग, निवेशकों और शिक्षण संस्थानों को एक मंच पर जोड़ते हुए डीप टेक नवाचार के प्रमुख केंद्र बनेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को नई तकनीकों का केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स आने वाली औद्योगिक क्रांति के प्रमुख आधार हैं। इसलिए एक ओर विश्वस्तरीय विनिर्माण अवसंरचना विकसित की जाए तो दूसरी ओर अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाला मजबूत डीप टेक इकोसिस्टम तैयार किया जाए। उद्योग, शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों, स्टार्टअप, निवेशकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जहां नई तकनीकें तेजी से प्रयोगशाला से उद्योग तक पहुंच सकें और उत्तर प्रदेश वैश्विक प्रौद्योगिकी निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे।

बैठक में बताया गया कि इसी उद्देश्य से नोएडा में लगभग 75 एकड़ क्षेत्रफल में प्रगति अर्थात पार्क फॉर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीयू क्लस्टर्स एंड एडवांस्ड टेक्निकल इनोवेशन विकसित किया जाएगा। यह भारत का पहला एकीकृत रोबोटिक्स एवं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा, जहां रोबोटिक्स परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र, रैपिड प्रोटोटाइपिंग एवं विनिर्माण सुविधा, एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, मोशन कैप्चर लैब, फिजिकल एआई डेटा सेंटर, स्टार्टअप इनक्यूबेशन तथा को वर्किंग स्पेस जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही वैश्विक विनिर्माण कंपनियों, कंपोनेंट निर्माताओं, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों तथा विशेषीकृत सेवा प्रदाताओं का समग्र औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र भी विकसित किया जाएगा।

बैठक में यह भी बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रक्षा औद्योगिक गलियारा तथा मजबूत औद्योगिक एवं शैक्षणिक आधार के कारण नोएडा इस परियोजना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। परियोजना का उद्देश्य प्रदेश को रोबोटिक्स एवं उच्च प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण का राष्ट्रीय केंद्र बनाना, आयात पर निर्भरता कम करना, एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना तथा अगले पांच वर्षों में लगभग दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का सकल मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना है।

स्थानीय समाचार

विक्रमादित्य ने सोज़ के जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय संबंधी बयान को ऐतिहासिक रूप से गलत बताया

जम्मू 7 16 जुलाई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज़ द्वारा हाल ही में दिए गए उस बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय इसलिए हुआ क्योंकि राज्य की मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी ने ऐसा चाहा था, पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व एमएलसी एवं महाराजा हरि सिंह के पौत्र विक्रमादित्य सिंह ने इसे ऐतिहासिक रूप से गलत, अविवेकपूर्ण और अनावश्यक करार दिया है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय को केवल धार्मिक पहचान के आधार पर प्रस्तुत करना न केवल इतिहास को विकृत करना है, बल्कि उस संवैधानिक प्रक्रिया को भी कमजोर करना है जिसके माध्यम से 560 से अधिक रियासतों का भारत में विलय हुआ था।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा, जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय धार्मिक गणित या बहुसंख्यक भावना के आधार पर नहीं हुआ था। यह उस समय के राज्य के संप्रभु शासक द्वारा विधिसम्मत रूप से निष्पादित इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे अन्य रियासतों का भारत में विलय हुआ। इस स्थापित ऐतिहासिक तथ्य को बदलने का कोई भी प्रयास केवल भ्रम पैदा करेगा और तथ्यपरक सार्वजनिक विमर्श को कमजोर करेगा।

पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम

सांबा, 16 जुलाई (हि.स.)। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन-विकास एवं सुविधा कार्यालय जम्मू ने जिला प्रशासन सांबा के सहयोग से आज जिला प्रशासनिक परिसर के सम्मेलन कक्ष में पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों, कारीगरों और उद्यमियों को ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय समावेशन, उत्पाद पैकेजिंग, सरकारी सहायता योजनाओं और उद्यमिता विकास के बारे में जागरूक करना था ताकि वे बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और आय सृजन को बढ़ा सकें।

कार्यक्रम का शुभारंभ जम्मू के सहायक निदेशक अरविंद कुमार शर्मा के परिचयात्मक भाषण से हुआ जिन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना का संक्षिप्त परिचय दिया।

उन्होंने कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, ब्रांडिंग और बाजार संपर्क सहित संपूर्ण सहायता के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

18 जुलाई से श्रीनगर में शुरू होगा 9 दिवसीय चिनार पुस्तक महोत्सव

श्रीनगर, 16 जुलाई। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में 18 जुलाई से 26 जुलाई तक तीसरे चिनार पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने इसकी जानकारी दी।

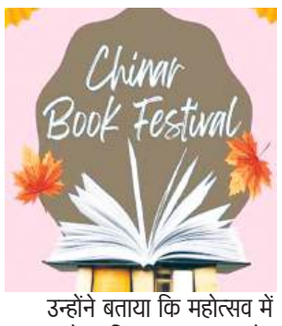

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) द्वारा आयोजित यह नौ दिवसीय महोत्सव कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (पूर्व में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर) में आयोजित होगा।

एनबीटी के निदेशक युवराज मलिक ने श्रीनगर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि यह महोत्सव देशभर के पाठकों, लेखकों, प्रकाशकों और कलाकारों को साहित्य, संवाद और सांस्कृतिक उत्सव के लिए एक मंच पर लाएगा।

उन्होंने बताया कि महोत्सव में 200 से अधिक प्रकाशक और पुस्तक स्टॉल भाग लेंगे, जहां अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का प्रदर्शन किया जाएगा।

पुस्तक महोत्सव के दौरान साहित्यिक परिचर्चाएं, लेखकों से संवाद, पुस्तक विमोचन, कार्यशालाएं, कहानी सत्र, बच्चों के लिए रचनात्मक गतिविधियां तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

महोत्सव का उद्घाटन जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध विद्वान एवं शिक्षाविद हफीजुर रहमान की पुस्तक एन इंडियन मुस्लिम स्पीक्स का विमोचन भी किया जाएगा।

महोत्सव का एक अन्य प्रमुख आकर्षण पिछले संस्करण के दौरान आयोजित पहली ग अनुवाद कार्यशाला के माध्यम से तैयार की गई 24 द्विभाषी पुस्तकों का विमोचन होगा।

इसके अलावा, राजतरंगिणी कार्यशाला के अंतर्गत विकसित उपन्यासों की पहली श्रृंखला का भी लोकार्पण किया जाएगा।

महोत्सव में बच्चों के लिए विशेष चिल्ड्रन्स कॉर्नर बनाया जाएगा, जहां रचनात्मक कार्यशालाएं, कहानी सत्र और विभिन्न इंटरैक्टिव गतिविधियां आयोजित होंगी। साथ ही, आगंतुक राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय का भी लाभ उठा सकेंगे, जहां विभिन्न विषयों और भाषाओं की हजारों ई-पुस्तकें नि:शुल्क उपलब्ध होंगी। इस वर्ष का एक विशेष आकर्षण 5के रीडिंग रन - टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड होगा।

यह श्रीनगर में अपनी तरह का पहला आयोजन होगा, जिसका उद्देश्य पुस्तकों के प्रति रुचि और फिटनेस को एक साथ बढ़ावा देना है। इसमें हजारों स्कूली विद्यार्थियों के भाग लेने की उम्मीद है। श्रीनगर के उपायुक्त अक्षय लबरू ने कहा कि यह महोत्सव सभी के लिए खुला रहेगा और इसमें प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क होगा। उन्होंने कहा, हमने पहले दो संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किए थे।

महानपुर का पटवारी 10 हजार की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

कठुआ, 16 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का महानपुर (कठुआ) के पटवारी खजान चंद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पटवारी पर म्यूटेशन से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है।

एसीबी के अनुसार इस संबंध में थाना एसीबी जम्मू में एफआईआर संख्या 05/2026 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पटवारी खजान चंद ने उसकी बहन के पक्ष में म्यूटेशन दर्ज करने के बाद संबंधित दस्तावेज देने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। बताया गया कि शिकायतकर्ता पहले ही 9,000 रुपये आरोपी को दे चुका था जबकि शेष राशि के रूप में 11,000 रुपये की मांग की जा रही थी। बाद में यह सौदा 10,000 रुपये पर तय हुआ। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था इसलिए उसने एसीबी से संपर्क कर कानूनी कार्रवाई की मांग की।

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने गुप्त जांच की जिसमें रिश्वत मांगने के आरोप सही पाए गए। इसके बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाया और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी पटवारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। एसीबी टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली। इसके अलावा आरोपी के आवास पर भी स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी अभियान चलाया गया। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और इस प्रकरण में अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

उप आयुक्त राज्य कर (रिकवरी) ने वसूली कार्यवाही की समीक्षा की, जीएसटी/वैट बकाया की शीघ्र वसूली पर दिया जोर

जम्मू, 16 जुलाई। उप आयुक्त राज्य कर (रिकवरी), जम्मू सपना कोतवाल ने आज पुरानी जीएसटी, वैट तथा नई जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत चल रही वसूली कार्यवाहियों की प्रगति की समीक्षा करने तथा सरकार के बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान उप आयुक्त ने पिछले दो महीनों में की गई वसूली की प्रगति का आकलन किया और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भीतर तथा बाहर दोनों स्थानों पर वसूली कार्यवाहियों में हुई उल्लेखनीय प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने रिकवरी विंग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए किए जा रहे समर्पित प्रयासों की सराहना की।

वसूली की गति को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए सपना कोतवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वसूली प्रयासों मेंऔर तेजी लाएं, लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें तथा सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए परिणामोन्मुख और केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी वसूली कार्यवाहियां संबंधित कर कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप, पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही तथा आवश्यकतानुसार केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए की जाएं।

29 जुलाई को निकलेगी छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की वार्षिक पवित्र यात्रा

श्रीनगर, 16 जुलाई। छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरि ने गुरुवार को दक्षिण कश्मीर हिमालय में जारी अमरनाथ यात्रा के दौरान भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक की वार्षिक यात्रा की घोषणा की।

महंत दीपेंद्र गिरि ने एक बयान में कहा कि प्राचीन परंपरा के अनुसार भूमि पूजन, नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण जैसे धार्मिक अनुष्ठान, जो छड़ी मुबारक की वार्षिक यात्रा की पारंपरिक शुरुआत से जुड़े हैं, आषाढ़ पूर्णिमा (व्यास पूर्णिमा) के शुभ अवसर पर 29 जुलाई (बुधवार) को पहलगाम में संपन्न किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त को छड़ी मुबारक को शंकराचार्य मंदिर ले जाया जाएगा तथा 13 अगस्त को शारिका भवानी मंदिर में पूजा-अर्चना की जाएगी। इसके बाद 15 अगस्त को श्री अमरेश्वर मंदिर, दशनामी अखाड़ा, श्रीनगर में छड़ी स्थापना का अनुष्ठान किया जाएगा। महंत ने बताया कि 17 अगस्त को नाग पंचमी के शुभ अवसर पर दशनामी अखाड़ा, श्रीनगर में पारंपरिक छड़ी पूजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को मुख्य यात्रा प्रारंभ होगी और पवित्र छड़ी मुबारक को स्वामी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा, जहां 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पूजा-अर्चना और पवित्र दर्शन किए जाएंगे।यात्रा के दौरान 22 और 23 अगस्त को पहलगाम, 24 अगस्त को चंदनवाड़ी, 25 अगस्त को शेषनाग तथा 26 और 27 अगस्त को पंचतरणी में रात्रि विश्राम किया जाएगा।

थाली से आगे: न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी और मन-शरीर के गहरे रिश्ते को समझना

अमीर इक़बाल ख़ान

मनोविज्ञान विज्ञान की उन चुनिंदा शाखाओं में से एक है, जिसकी 70 से अधिक विशिष्ट उपशाखाएँ हैं। रसायन विज्ञान जैसे विषय जहाँ नए यौगिकों के निर्माण पर केंद्रित रहते हैं, वहीं मनोविज्ञान मूलतः खोज का विज्ञान है। यह मानव व्यवहार, सोच और व्यक्तित्व के उन पहलुओं को समझने का प्रयास करता है, जो सदियों से हमारे भीतर मौजूद हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण शाखाओं में एक है न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी (पोषण मनोविज्ञान), जो यह अध्ययन करती है कि भोजन के साथ हमारा संबंध हमारे मन, व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है।

हालाँकि भोजन और स्वास्थ्य का संबंध प्राचीन काल से स्वीकार किया जाता रहा है, लेकिन न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी का वैज्ञानिक अध्ययन अपेक्षाकृत नया है। सरल शब्दों में कहें तो यह खाने के मनोविज्ञान का अध्ययन है। इसका केंद्र केवल यह जानना नहीं है कि आपकी थाली में क्या है, बल्कि यह समझना भी है कि आप कितना खाते हैं, कब खाते हैं, किस वातावरण में खाते हैं और भोजन

करते समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। यही खाने का व्यवहार (Eating Behavior) हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालता है।

न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले इस विचार को स्वीकार करना आवश्यक है कि भोजन ही सबसे पहली औषधि है। यदि भोजन को सजगता और संतुलन के साथ ग्रहण किया जाए, तो वह शरीर को ऊर्जा देता है, रोगों से बचाता है और मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है। इसके विपरीत, असंतुलित भोजन धीरे-धीरे शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुँचाता है।

दुर्भाग्य से आज की जीवनशैली, विशेषकर हमारे स्थानीय खान-पान में, इस सिद्धांत से दूरी साफ दिखाई देती है। अक्सर लोग अत्यधिक मसालेदार, तला-भुना या भारी भोजन करते हैं और फिर उससे होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए कोल्ड ड्रिंक, सोडा या अन्य चीज़ों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, चिकन करी जैसे भारी व्यंजन खाने के तुरंत बाद कार्बोनेटेड पेय पीना कई लोगों की आदत बन चुकी है। इसी तरह दाल-रोटी जैसे संतुलित भोजन के साथ अनावश्यक अतिरिक्त व्यंजन शामिल कर लेना और बाद में अपच की दवा तलाशना भी आम बात है।

सवाल यह है कि हम ऐसा भोजन क्यों नहीं चुनते जिसे पचाने के लिए किसी अतिरिक्त सहारे की आवश्यकता ही न पड़े? इसका उत्तर हमारे खाने के व्यवहार में छिपा है और हर व्यवहार की शुरुआत मन से होती है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी व्यवहार की शुरुआत पहले भावना से होती है। भावना विचार को जन्म देती है और विचार अंततः व्यवहार में बदल जाता है। इसलिए यदि भोजन के प्रति हमारी सोच बदल जाए, तो खाने की आदतें भी स्वतः बदलने लगती हैं। भोजन के प्रति सकारात्मक और जागरूक दृष्टिकोण अपनाने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक संतुलन भी मजबूत होता है।

कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जिन्हें समझना आवश्यक है

पोषण (Nutrition) और भोजन (Food)पोषण केवल एक वैज्ञानिक विषय नहीं, बल्कि वह जैविक प्रक्रिया भी है जिसके माध्यम से हमारा शरीर भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उन्हें अवशोषित करता है और उनका उपयोग करता है। वहीं, भोजन (Food) वह वस्तु है जिसे हम खाते हैं, जैसे बिरयानी, बर्गर, दाल-रोटी या सेब। सरल शब्दों में, भोजन वह है जिसे हम खाते हैं, जबकि पोषण वह प्रक्रिया है जो उसे शरीर के लिए उपयोगी बनाती है।

बिरयानी या कोई अन्य व्यंजन भोजन है, लेकिन उसके भीतर मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। यही सूक्ष्म तत्व हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए वास्तविक ईंधन का काम करते हैं।

जब किसी भोजन को दिन के निश्चित समय—जैसे नाश्ता, दोपहर का भोजन या रात्रि भोजन—के रूप में लिया जाता है, तब वह आहार (Meal) कहलाता है।

'क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू' अभियान के तहत जेएमसी ने शांति पार्क में मेगा पौधारोपण अभियान चलाया

जम्मू, 16 जुलाई । जम्मू नगर निगम (जेएमसी) ने अपने क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत वार्ड संख्या-61 (पट्टा पलौड़ा) स्थित शांति पार्क में एक मेगा पौधारोपण अभियान आयोजित किया। इस अभियान का शुभारंभ जम्मू नगर निगम के आयुक्त डॉ. देवांश यादव ने किया।

शहरी वानिकी प्रभाग, जम्मू के सहयोग से आयोजित यह अभियान डॉ. देवांश यादव के नेतृत्व में चलाए जा रहे शहरव्यापी हरित अभियान का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य जम्मू शहर में 50,000 से अधिक पौधे लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर के हरित क्षेत्र का विस्तार करना, वायु गुणवत्ता में सुधार लाना, जैव विविधता को बढ़ावा देना तथा जनभागीदारी के माध्यम से अधिक टिकाऊ शहरी वातावरण विकसित करना है।

अभियान के दौरान शांति पार्क में लगभग 2,100 पौधे लगाए गए, जिससे शहर को एक नया हरित क्षेत्र प्राप्त हुआ। यह पौधारोपण कार्यक्रम शहरी प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक स्थलों के विकास की दिशा में जम्मू नगर निगम के प्रयासों का हिस्सा है।

डॉ. देवांश यादव ने कहा कि शहरी वानिकी पर्यावरणीय स्वास्थ्य तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने नागरिकों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों तथा युवा समूहों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने और लगाए गए पौधों की देखभाल एवं संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने की अपील की, ताकि उनकी बेहतर वृद्धि और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त (स्वास्थ्य एवं स्वच्छता) अब्दुल सत्तार, उप आयुक्त (उत्तर), जेएमसी संजय बड़याल, प्रभागीय वन अधिकारी जम्मू अश्विनी शर्मा, सहायक पुष्पकृषि अधिकारी डॉ. राबिया खान, पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक डॉ. प्रियंका मल्होत्रा, पूर्व पार्षद मोहिंदर कुमार सहित जम्मू नगर निगम एवं शहरी वानिकी प्रभाग के अधिकारी, वरिष्ठ नागरिक, स्वयंसेवक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।